

Vol. II  
No. 21



Friday  
17th September, 1954

# HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES

## Official Report

### PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

#### CONTENTS

	PAGE
Presentation of the Report of the Committee on unemployment and under employment .. .. .	1059
L. A. Bill No. XXXIV of 1954, the Hyderabad Pathology Bill 1954 — Introduced .. .. .	1059
Discussion on the Revenue Department Notification No. 58 dated 2-9-1954—not concluded .. .. .	1059-1107
Half-an-hour debate .. .. .	1107-1114

*Note:—* \* at the commencement of the speech denotes confirmation not received.



# THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

*Friday, the 17th September, 1954*

The House met at Half Past Two of the Clock.

[MR. SPEAKER IN THE CHAIR]

## Questions and Answers

(See Part I)

### Presentation of the Report of the Committee on Unemployment and Under-employment

*The Minister for Public Works and Labour (Dr. G. S. Melkote)* : I beg to present the Report of the Committee on Unemployment and Under-employment.

*Mr. Speaker* : The report is presented.

*Dr. G. S. Melkote* : This Committee was constituted by the Hyderabad Legislative Assembly on 18th July, 1952. The report presented to the House includes a note of dissent by three hon. Members of the Committee namely Shri B. D. Deshmukh, Shri V. D. Deshpande and Shri Annaji Rao Gavane. While presenting this report I have to acknowledge with thanks the valuable services rendered by my colleagues in drawing up this report.

### L. A. Bill No. XXXIV of 1954, the Hyderabad Pathology Bill, 1954

*The Minister for Medical, Public Health and Rural Reconstruction (Shri Mehdi Nawaz Jung)* : I beg to introduce:

“L. A. Bill No. XXXIV of 1954, the Hyderabad Pathology and Anatomy Bill, 1954”.

*Mr. Speaker* : The Bill is introduced.

**Discussion on the Revenue Department Notification No. 53, dated 2-9-1954; re: Land Commission Report.**

श्री रामगोपाल रामकिशन नावंदर (कन्नड) :— तारीख १३ को अंक मोशन रेविन्यू डिपार्ट-मेंट के नोटीफिकेशन के लिहाज से यहां मूव्ह किया गया और आज अंस पर बहस शुरू हो रही है। यह मसला बहुत अहम है जिसलिये हाउस के इस जानिब के और अंस जानिब के, और खास तौर पर इस जानिब के भी आनरेबल मॅम्बर्स में इसके बारे में बुनियादी अखतलाफ नजर आता है। . .

شری کے - وی - نارائن ریڈی ( راج گویال پیٹھ ) : — مسٹر اسپیکر سر - میں اس رپورٹ کے صفحہ (۹۶) کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں - اس میں تھوڑی سی غلطی ہے - یہاں ”وائڈ پیارا“ ( Vide para ) (۱۲۴) کی بجائے پیارا (۱۲۱) ہونا چاہئے - اوسکے بعد دوسرے سنٹنس میں ”ان پیارا“ ( In para ) (۱۸۰) کی بجائے (۱۷۱) ہونا چاہئے۔

श्री. रामगोपाल रामकिशन नावंदर :—जिस नोटीफिकेशन के लिहाज से लैंड कमीशन टेनन्सी ऑड अग्रिकल्चरल अॅक्ट १९५० की दफा ८७ के तहत कायम किया गया था और अन्होंने यह रिपोर्ट दफा ३ और ४ के सूचनाओं को सामने रखते हुअे की है और जिस को ध्यान में रख ते हुअे अन्होंने फॅमिली होल्डिंग और इसके तमाम चीजों की जानकारी हासिल कर के फॅमिली होल्डिंग और लोकल अेरिया तय कीये है। इसके बावजूद हम लोगों में जिस जमीन के मसले पर अंक्तिलाफ है। लेकिन वह बहस अब जिस जगह नहीं होसकती क्योंकि वह कानून के बनते वक्त हो चुकी है और उसके बाद यह कानून यहां पर आ गया है। जिस कानून की दफा के तहत लैंड कमीशन ने छः महीने के मुकररा वक्त में यह काम किया है। कमीशन ने बहुत मेहनत कर के, दौरा कर के, बहुत से लोगों से मशविरा करके अंक अैसी रिपोर्ट पेश की है जिसको पढने पर यह कहने लिये के तामूल नहीं होना चाहिये कि कानून के स्पिरिट ( Spirit - ) को बहुत हद तक इंप्लिमेंट ( Implement ) करने के लिहाज से आसान कर के यह पेश की गयी है। जिस-लिये हम अूनको धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकते। हमारे मुल्क का यह बहुत बडा मसला है। हर पार्टी और हर किसमके के लोग जिस मसले को अंक बुनियादी मसला समझते हैं। जिराअत की तरक्की के सिलसिले में अूनके खियालात अलग अलग हो सकते हैं लेकिन जिससे अंखितलाफ नहीं हो सकता कि यह अंक बुनियादी मसला है। मुल्क की आजादी को हासिल करने के बाद हमें अपनी आर्थिक अस्वाजादी को हासिल करना है। हमें जिसको अच्छी तरीके से हल करना चाहिये। जिस लिहाज से जो कानून बनाया गया है उसकी रोशनी में जितनी जल्द और आसानी से हो सके अतनी जल्द अुसे इम्प्लीमेंट कर सकें, जिसलिये यह रिपोर्ट पेश की गयी है। जिस मसले को हल करते वक्त बहुत से लोगों का ख्याल था कि आनवारी को बेसिस करार न देते हुअे लैंड रेवीन्यू को बेसिस समझें, लेकिन यह बात कानून बनाते वक्त नहीं मानी गयी। पूरी रिपोर्ट और आखिरी रेकमॅडेशन ( Recommendation ) पढने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अितना खर्च और मेहनत करने के बाद, तीन चार हजार लोगों के देहातों में धूमकर स्टेटमेंट लेने के बाद कमीशन ने वही राय दी थी जो कानून बनते वक्त हावुस ने दी थी। जिस लिहाज से जिस मामले को आसानी से हल करने के लिये लैंड रेवीन्यू बेसिस करार दिया जाता तो मुनासिब होता, लेकिन वक्त गुजर चुका और रिपोर्ट कानून की दफा ४ के तहत हमारे सामने पेश की गयी है। करीब २०० सप्पे की यह रिपोर्ट है। जिसमें से चंद चीजों पर मैं अपने ख्यालात पेश करूंगा। जिस मसले

पर हमें जरा शांति से सोचना चाहिये। मुल्क में आज तक इस मसले को हल करने की कभी कोशिशें हुईं, कुछ कामयाब हुईं कुछ नाकामयाब रहीं। हैद्राबाद में भी इस तरह की कोशिश हुई और कुछ तृटियों के साथ क्यों न हो लेकिन अक प्रोग्रेसिव्ह ( *Progressive* ) कानून हमने बनाया। और उसके नतीजे के तौर पर यह रिपोर्ट हमारे सामने आती है। जमीन का मसला हल करते वक्त जमीन पर जिन चीजों का असर होता है उन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। जमीन में कभी तरह के भेद होते हैं। आनेवारी के हिसाब से देखें तो सैंकड़ों अकसाम हो जायेंगे। उसके लिहज से फैमिली होल्डिंग और लोकल अरियाज तय करना बहुत मुश्किल होजाता है। जमीन कभी रंगों की होती है, काली, लाल, मुरमट और पथरीली भी होती है। जमीन के रंग के साथ साथ उनकी गहराई भी देखनी पड़ती है। जिस जमीन की गहराई ६ अंच है उसका उत्पादन उस जमीन से कम होगा जिसकी गहराई दो या तीन फीट है। साथ साथ यह भी देखना पड़ता है कि जमीन में कैल्शियम ( *Calcium* ) या दूसरे क्षार द्रव्य किस प्रमाण में हैं। इन तमाम चीजों की वजह से जमीन की ताकत कम ज्यादा होती है। लैंड कमिशन ने इन तमाम चीजों का ख्याल रखकर उसके ऊपर अपनी तफसीली रिपोर्ट पेश की है। इसके साथ साथ जब हम जमीन के मसायल को देखते हैं तो बारिश कहां कितनी होती है, उसको भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस लैंड प्रॉब्लेम ( *Land Problem* ) पर पानी का बहुत ज्यादा असर होता है। हमारे प्रदेश के कुछ हिस्सों में १० अंच से लेकर ज्यादा से ज्यादा ४० अंच तक बारिश होती है जिसलिये पैदावार में हर साल फर्क होता रहता है। बारिश ठीक हुई तो पैदावार अच्छी होती है, कम या ज्यादा हुई तो फसल खराब हो जाती है।

असके बाद दूसरा मसला आबोहवा का होता है। आबोहवा पर बहुत फसलें मुनहसिर होती हैं। इसे भी हमें नहीं भूलना चाहिये। आबोहवा के लिहाज से पैदावार अलग अलग होती हैं। अक ही किसम की जमीन में अक जगह जवारी होती है तो दूसरी जगह नहीं होती, ऐसा क्यों होता है ? इसका कारण यह है कि जमीन अक सी है लेकिन दोनों जगहों की आबोहवा अकसी नहीं है। जवारी के लिये जिस तरह की आबोहवा की जरूरत है वैसी किसी स्थान पर न रहने के कारण वहां जवारी नहीं हो सकती। अक जगह गेहूं होता है दूसरी जगह वह नहीं होता, इसकी वजह भी आबोहवा ही है। वरंगल और औरंगाबाद में दोनों जगह अक ही किसम की काली जमीन है, लेकिन औरंगाबाद में कपास होती है और वरंगल में वह नहीं होती। जमीन अकसी होने पर भी ऐसा क्यों होता है ? इसकी वजह यही है कि दोनों स्थानों का हवामान अलग अलग है। यही बड़े पेचीदे मसले जमीन का मसला हल करते वक्त हमारे सामने आते हैं। इसी को ख्याल में रखकर लैंड कमिशन ने अपना रिपोर्ट पेश किया है।

असके बाद हमारे सामने हालात का मसला आता है। हालात यानी जो काश्तकार खेती करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति का भी लिहाज यहां पर करना पड़ता है। आजकल हम बहुत ही जल्द मशीन युग की तरफ जा रहे हैं। आज का युग ही मशीन युग कहलाता है और हर अक काम में आज हम मशीन का अिस्तेमाल करने की कोशिश कर रह हैं। उसी तरह से आज हम खेती में मशीनों का अपुयोग करने लगे हैं। आजकल खेती में ट्रैक्टर ( *Tractor* ) का अपुयोग करने लगे हैं। लेकिन सब जगह आज भी ट्रैक्टर का अिस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि

सब को ट्रक्टर लेने की आज भी शक्ती नहीं है और वे नहीं ले सकते हैं। आज भी कहीं जगह वही पुराने नांगरोंसे काम लिया जा रहा है। कहीं जगह आज भी वही पुराने लकड़ी के नांगरों से खेती की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि हर जगह अक ही किसम के औजारों का इस्तेमाल नहीं होता है। अलग अलग स्थान पर अलग अलग किसम के औजार काम में लाये जाते हैं, और असी पर पैदावार का प्रमाण अवलंबित रहता है। अक ही किसम की जमीन पर यदि आप अलग अलग तरह औजारोंका इस्तेमाल करें तो अलग अलग तरह की पैदावार होती है। कहीं पैदावार ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है। इस लिये फॅमिली होल्डिंग का और लोकल ( Local area ) का तायुन करते वक्त इन सब बातों का लिहाज किया जाना चाहिये। बाजार भाव भी कम ज्यादा हुवा करते हैं, अन्हें भी इन बातों को सोंचते समय ब्याल में रखना पडता है। १६०० रुपये का जो इनकम रखा गया है उसमें पचास परसेंट खर्चा जाता है और नेट इनकम ८०० रुपये का होता है, ऐसा माना गया है। लैंड कमिशन ने जो फॅमिली होल्डिंग तय किया है उसमें बताया है कि फॅमिली होल्डिंग जो भी रखा गया है उसमें डेढ गुना का बिजाफा करना जरूरी है। जिसके बारे में सोंचा जाना चाहिये। लैंड कमिशन ने यह कोशिश की है कि आसान से आसान तरीके हों और उसमें कॉम्प्लिकेशन ( Complication ) न हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि आसान से आसान तरीका निकालते समय जिस अँकट का जो मकसद था वही फौत हो रहा है। आपको

### “Below eight annas and above eight annas”

जिस तरह का क्लासिफिकेशन ( Classification ) करना जरूरी था लेकिन अु तरह से नहीं किया गया। फॅमिली होल्डिंग तय करते वक्त जिसका लिहाज किया जाना चाहिये था, लेकिन आज लैंड कमिशन के रिपोर्ट से जो चीज नजर आ रही है वह बिल्कुल ही नयी है। जिसमें तो कानून का जिसके बारे में जो नजरीया था अुसे ही खतम किया गया है। अलग अलग किसम सॉबिल की होती है, अुसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। जिससे यही होगा की आपन जिस मकसद से यह कानून लाया है वह पूरा नहीं होगा और लोगों को जमीन कम मिलेगी, और लोगों पर ज्यादा अन्याय होगा। जिसका लाजमी नतीजा यही होगा की अुसका असर प्रोटेक्टेड टेनंट सब टेनंट, टेनंट्स आदि सब पर पडेगा। और जो भी व्यक्ति का जमीन से तालुक होता है अुन सब पर जिसका असर पडना लाजमी है। इन तमाम चीजों को सोंचा जाना चाहिये था। जमीन के टुकड़ों का भी मसला यहीं पर आजाता है। रोटेशन ( Rotation ) कल्चिवेशन ( Cultivation ) और सुपरविजन ( Supervision ) यह फॅक्टर्स हैं जिनका असर अुपजपर होता है। यदि जमीन का टुकड़ा ज्यादा बड़ा रहा तो काश्तकार अुसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता है, अगर वह अकेला हो और कंपैरेटिव्हली ( Comparatively ) अुसकी आमदनी कम होजाती है, और अॅवरेज अीलड ( Average yield ) घट जाती है। पैसे ज्यादा खर्च करने पडते हैं और अुसके बनिसबत आमदनी कम होजाती है, और अॅवरेज अिन्कम भी कम होजाता है। इन हालात के लिहाज से लैंड कमिशन ने जो रैकमेंडेशन्स दिये हैं वही सही हैं। इन हालात में कानून के मसलों और दूसरे तमाम मसलों की तरफ नहीं देखा जाना चाहिये। यह कानून ही अितना पेचीदा है और यह मसला भी अितना पेचीदा है कि अच्छे अच्छे वकील और तालीमयाफता लोग भी जिसे अभी तक बराबर नहीं समझ

पाये हैं। ऐसी हालत में काश्तकार जो बिचारा अनपढ़ है और जो देहातों के लोग हैं वह इसे किस तरह समझ सकेंगे ? जिसमें जो टेबल आदि दिये हैं वे समझाना जिन लोगों के लिये नामुमकिन ही होगा। जिस कानून से जमीन के मसले को हल करने की जो कोशिश की जा रही है और जो रिफार्म लाया जा रहा है और उसके तहत जो जमीन मिलनेवाली है और जिसके पहले जिनको गैर कानूनी अख्तियार मिले थे उसे अकेल खतम करने के लिये हमारे पास आज जो रिपोर्ट आती है उसके बाद अब जिस कानून को फौरन अमल में लाना चाहिये, तो इसके नतायज अच्छे होंगे और जिसका मकसद पूरा होगा। जिसकेबिना लोग इससे मुतमयीन न होंगे कि जिस कानून के जरिये से सचमुच ही जमीन मिल सकती है। जिससे आज जो चेक्स अन्ड बान्ड्स ( Checks & Bonds ) हैं वे खतम होंगे। और जिसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट ( Implement ) करने की जरूरत है। आज बड़ेबड़े जमीनदारों के पास जो जमीन है, वह काश्तकारोंको मिलनी चाहिये। किसको कम या किसको ज्यादा जमीन मिलेगी यह महत्वका सवाल नहीं है, लेकिन पहले अन्हें कुछ न कुछ जमीन मिलनी चाहिये ताकि अन्हें मालूम हो सकें कि जिस कानून से भी जमीन मिल सकती है, और अंनको यह मालूम होगा कि जिस कानून के तहत जमीन बटना शुरू होगी है। लेकिन यदि ज्यादा हिस्से पड़ते हैं तो उसके लिये हमें चेक लगाना चाहिये। आज हमारी जमीन के काश्तकार कभी तरह के हैं। टेनंट्स हैं, शिकमीदार हैं, प्रोटेक्टेड टेनंट्स हैं, और लैंड रेविन्यू लेने की रयतवारी सिस्टिम कभी जगह नाफिज है। रयतवारी सिस्टिम में जमीनदार काश्तकारों को लूटते हैं। जिस कानून के बाद अन्हे कम मौके रहेंगे।

पहले कहा जाता था कि लैंड रेविन्यू बेसेस ( Land Revenue basis ) अच्छा नहीं है, लेकिन अब कमिशन ने कभी जगह उसे माना है जमीन की बहुत से किसमें हैं और अलग अलग किसम की जमीनें अेकही मुकमात पर हैं, जिसको सोचकर लैंड कमिशन ने यह तसफिया किया है।

जिसका तायुन करते वक्त वे रेविन्यू सर्कलतक गये हैं। मेरा तो कहना है कि लैंड कमिशन देहात में जाकर देखभाल करता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि यह मसला अितना पेचीदा है कि रेविन्यू सर्कल बहुत बड़े बड़े बनाये गये हैं। अेक अेक तालुके के रेविन्यू सर्कल बनाया गया है और उसमें अलग अलग किसम की जमीनें आती हैं, जिस लिये अेक किसम की जमीन देखर जरूरत हो तो रेविन्यू सर्कल को स्प्लिटअप ( Split up ) भी किया जा सकता है। लेकिन यह कहा गया कि जिस तरह से उसे स्प्लिट अप नहीं किया जा सकता है, और यह सही भी है। जिस तरह से इसे स्प्लिट अप करने के लिये जो कहा जा रहा है, वह सही नहीं होगा, और लैंड कमिशन ने जो लोकल अेरियाज बनाये हैं वह काफी ठीक हैं।

लैंड कमिशन ने और दूसरी जो रेकमेंडेशन्स ( Recommendations ) की हैं वह भी काफी अच्छी हैं। फॅमिली होल्डिंग ( Family holding ) का तायुन करते वक्त लैंड कमिशन ( Land Commission ) ने साधारणतः २१ अेकड़ जमीन इसके लिये रखी है, और यदि कौड़ी जमीन अिरीगेशन के तहत हो तो उसके लिये ज्यादा से ज्यादा ६० अेकड़ रखा गया है। वर्क युनिट का लिहाज फॅमिली होल्डिंग और वक्त युनिट

अकही नहीं हो सकता है क्योंकि फॅमिली होल्डिंग यदि छोटा हो तो अक वर्क यूनिट में २ फॅमिली होल्डिंग्स भी आ सकते हैं, लेकिन हमने जिस में दूसरी बात भी रखी है। वह १६०० रुपये की आमदनी की है। फॅमिली होल्डिंग बनाते वक्त जिसका लिहाज किया गया है।

जिसके बाद लॅन्ड कमिशन ने अलग अलग अक्साम की जमीनात के बारे में जो बतलाया है उसके बारे में अक टेबल बनाकर हमारे सामने रखा गया है। और जमीनात को अलग अलग अक्साम में तकसीम करने का बताया है। और उसका अक टेबल हमारे सामने रख दिया गया है। लेकिन लॅन्ड रेविन्यू के ऑफिस में हम जाते हैं तो जिसका कोबी पता नहीं लगता है। जिसमें यह बताया गया है कि ८ आबे की ऊपर की जमीन कौनसी है और आठ आबे के निचे की कौनसी है, लेकिन यह बताना प्रॅक्टिकली नहीं हो सकता, जिस लिये कमिशन ने अपने रिपोर्ट में यह नहीं बताया है। और सिप्लिसिटी के लिहाज से यह प्रॅक्टिकल भी नहीं होता है।

अक अक जगह दो दो अकसाल की जमीन है। जिस लिये काफी लॅटिट्यूड (Latitude) रखना पडा है। जिसमें काश्तकारों को नजात मिल सकती है। सादी जमीन के लिये यह अलग अलग रखा गया है लेकिन वेट लॅन्ड (Wet land) की हदतक जिस तरह से अलग अलग नहीं रखा गया है। सब वेट लॅन्ड के लिये ६ अकड से ९ अकड किया गया है। वेट लॅन्ड जो बावली के तहत रहते हैं, वहाँ वह आदमी खुद बावली खुदवाता है, खर्चा करता है और ज्यादा पैदावार पैदा करता है, जिस लिये उसे दूसरे जमीनात के मुमासिल रखा गया है। डबल क्राप जहाँ होता है, वहाँ पर ४ अकड रखा गया है, और जहाँ लाजिट जिरिगेशन होता है वहाँ लोकल अेरियाके लिये ५० परसेंट रखनेका रेकमेंडेशन किया गया है।

जिन तमाम रेकमेंडेशन्स के बाद और यह कानून के अमल करने के बाद काफी जमीन मिलेगी लेकिन वह यदि बंजर ही हो तो उससे कोबी फायदा नहीं होगा। जिसलिये यह जो रेकमेंडेशन्स हैं उन्हें जल्द से जल्द अमल में लाने की जरूरत है। जितना कहते हुआ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

मैस्टर اسپیکر:— میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ ڈسکشن کے لئے ٹائم لمٹ (Time limit) رکھنی چاہئے۔ ہر ممبر کو ۱۵ منٹ دئے جائینگے۔ ایسی صورت میں ہی زیادہ آنریبل ممبرس کو تقریر کا موقع مل سکیگا۔ اور کل بھی اس پر بحث ہوگی۔ غیر معمولی صورتوں میں ۲۰ منٹ کا وقت دیا جائیگا۔ اس سے زیادہ وقت نہیں دیا جاسکیگا۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (अजिप्पागुडा):—मेरे ख्याल से इसके लिये दो दिन रखे गये हैं और यह अक अहम मसला है। इसके लिये यदि कुछ टाइम ज्यादा दें तो मुनासिब होगा; क्योंकि शुरू में ही कुछ टाइम ज्यादा लगता है, बाद में कोबी नबी बात हो तो कही जा सकती है।

मैस्टर اسپیکر:— اسی وجہ سے تو میں نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ۲۰ منٹ لے سکتے ہیں۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—अध्यक्ष महोदय, आज हमारे हाजूस के सामने अक मोशन आया है जोकि लॅन्ड कमिशन के रिपोर्ट के बारे में है। जिस सिलसिले में जो तकरीरें हुयीं



शुनमें मैंने काफी कॉन्ट्राडिक्शन ( Contradiction ) पाया। जब मैं यह भाषण सुन रहा था तब मुझे हंसी अिस लिये आ रही थी कि किस तरह अेक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट किया गया है। अेक बार अेक बात कही गयी, अुसे बाद में कॉन्ट्राडिक्ट किया गया। अेक बार कहा गया कि लॅन्ड कमिशन जो कायम हुआ है वह सेक्शन ४ के तहत कायम हुआ है और दूसरे बार कहा गया कि असेसमेंट बेसिस ही अच्छा है, अैसा समझता हूं। फिर कहा गया कि हमने जो सेक्शन ४ को ड्राफ्ट किया है वही गलत है, अिस तरह से काफी कॉन्ट्राडिक्शन पाया गया, और यह देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। लॅन्ड कमिशन के कहने के मुताबिक तो हमने जो भी बातें कही हैं वह सब गलत हैं। असेसमेंट बेसिस, सॉजिल बेसिस, वेट लॅन्ड, ड्राय लॅन्ड, पांच आदमियों का फॅमिली युनिट (Family unit) जो भी हमने सेक्शन चार में बताया है वह सब लॅन्ड कमिशन के दृष्टि से गलत है तो फिर सही क्या है? क्या १६०० रुपये की आमदनी जो बेसिस बताया गया अुतना सही है और बाकी सब गलत है?

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

लॅन्ड कमिशन ने अिसके लिये बहुत मेहनत की और अपना काफी समय भी खर्च किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के वक्त अिस तरह अर्जुन ने द्रोणाचार्य को सिर्फ नमस्कार किया था वैसा ही यह हुआ है। मैं साफ बताना चाहता हूं कि लॅन्ड कमिशन ने जो अितनी मेहनत की लेकिन आखीर पहाड़ खोद के अुन्होंने अेक चूहाहि निकाला। लॅन्ड कमिशन ने जो काम आज हमारे सामने रखा है, वह तो हमारे सेटलमेंट डिपार्टमेंट के लोग भी ऑफिस में बैठकर यह काम कर सकते थे। अिसके लिये अितनी धूप और पानी में फिरने की क्या जरूरत थी? अिस तरह आपने अेरिया तय करके हमें बताया, अुस तरह यदि करना तो कोअी मुश्किल बात नहीं थी, और अितने काम के लिये कोअी लॅन्ड कमिशन मुकरर करने की भी जरूरत नहीं थी। अुनको भी यदि बेसिस बताया जाता तो वे भी अिसको कर सकते थे। हम तो पहले से ही बता रहे थे कि लॅन्ड रेविन्यू बेसिस ही रखना चाहिये। असेसमेंट बेसिस के लिये जब हम कह रहे थे तो अुसे नहीं माना गया और यह कहा गया कि अिसमें ज्यादा कॉन्प्लिकेशन होने के अिमकानांत हैं, अिस लिये अिसे नहीं माना जा सकता। और फिर आज अितना रूपया खर्च करने के बाद और अेक लॅन्ड कमिशन के रेकमंडेशन पर आखीर में अुसे मान लिया गया। आखीर में घूम फिर कर आप वहीं आये। आखिर पृथ्वी तो गोल ही है ना। लेकिन पहले ही अिसे मना जाता तो क्या होता? आज अिसे माना जा रहा है। अितना सब कर के आखिर में पहाड़ खोद कर चूहा ही निकला। मैं हुकुमत को बताना चाहता हूं कि अितना रूपया खर्च कर के और अेक लॅन्ड कमिशन नियुक्त कर के आपने कुछ भी हासिल नहीं किया और यह मैं सिद्ध करने के लिये भी तैयार हूं।

लॅन्ड कमिशन की जो रिपोर्ट है अुसके पेज २१ पर अुन्होंने कहा है कि पांच लोगों की कुनबे की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे लेकिन १६०० रुपये की आमदनी की जो शर्त है अुसी को हम ज्यादा महत्व देते हैं। प्लो युनिट ( Plough unit ) और वर्क युनिट ( Work unit ) का कोअी लिहाज नहीं किया गया है और यह कहा गया है कि यह ज्यादा कॉन्प्लिकेटेड है, अिस लिये अिसे नहीं माना जा सकता है। हम सिर्फ १६०० रुपये की आम-

बनो का ही ख्याल करेंगे अक्रेज का नायुन करते वक्त १६०० की आमदनी का ही लिहाज किया जायेगा। प्लोयुनिट के बारे में उन्होंने कहा है कि फॅमिली होल्डिंग के लिये यह लिमिट्स ( Limits ) नहीं लगाये जा सकते हैं। प्लोयुनिट में सुपरवाइजरी लॅन्ड लार्ड ( Supervisory Landlord ) आ जाता है, क्योंकि एक प्लो युनिट में एकही फॅमिली आयेगा, ऐसी बात नहीं है।

“The first condition therefore does not contain definition about the size of the holdings except perhaps for the implied sense regarding the maximum area which a family would be able to cultivate or supervise”.

अस लिये उन्होंने सुपरवाइजरी लॅन्ड होल्डर का बहाना लेकर १६०० रुपये की आमदनी का बेसिस ही अच्छा है, ऐसा कहा है।

“It is that piece of land which fetches a gross income annually of Rs. 1600.”

अन्होंने आखिर में यह बताने की कोशिश की है कि हमने जो यह सेक्शन ४ बताया है वह बिल्कुल बेकार है और इंप्रैक्टिकेबल ( Impracticable ) है। उसमें भी काफी डिफेक्ट्स ( Defects ) हैं, ऐसा उनका कहना है।

सॉइल के बारे में अन्होंने कहा है कि ब्लैक कॉटन सॉइल, चेलका सॉइल, रेड लॅन्ड, वेट लॅन्ड ( Black Cotton soil, Chalka soil, Red land, Wet land ) अस तरह हमने जो कानून के सेक्शन ४ में क्लासिफिकेशन ( Classification ) कर के दिखाया है, अन्होंने अॅग्रिकल्चर डिपार्टमेंट को हवाला देकर असे बेकार साबित करने की कोशिश की है। मिडिल क्लॉस सॉइल, खराब सॉइल पहाड़ के पास की जमीन, व्हाली के पास आनेवाली जमीन, असमें कुछ चेलका पाओ जाती है, कहीं वेट पाओ जाती हैं, लेकिन अिन सबका अेवरेज लेने के बारे में अन्होंने शिफारिस की है। यह अक्रेज की बात देखकर मुझे नदी की गहराई के अेवरेज की बात याद आगयी कि एक जगह नदी ४ फूट गहरी और दूसरी जगह ८ फूट गहरी है और तीसरी जगह २ फूट गहरी है तो अिनका अेवरेज निकाल कर बताया गया कि नदी साढेचार फूट से ज्यादा गहरी नहीं है और असमें कोअी असतरह से आरग्यूमेंट ( Argument ) करके असे नजर अंदाज कैसे किया जा सकता है? ब्लैक कॉटन सॉइल, चेलका सॉइल, अिनका धारा अैकसां कैसे हो सकता है, और अूनकी पैदावार भी अैकसां कैसे हो सकती है? अैकही जमीन में अैक जगह का सर्वे नंबर का असेसमेंट डेढ रुपया होगा दूसरी जगह का १ रुपया होगा और तीसरी जगह का ४ आने होगा, यह सबका अेवरेज लाकर कैसे चल सकता है? चार आने की यदी आप २४ अैकड जमीन छोड़ेंगे तो क्या डेढ रुपये की भी २४ ही अैकड जमीन छोड़ेंगे? यह अेवरेज का बेसिस सही नहीं है।

अेवरेज निकालना है तो पूरे मुल्क की हालत देखनी चाहिये। किंग कोठी के आसपास का अेवरेज निकालें तो वहाँ की आमदनी का अेवरेज काफी आयेगा लेकिन और किसी जगह का निका-

लेंगे तो वह बहुत कम हो जायगा क्योंकि वहां भिखारी भी बैठे हुवे हैं। जमीन जमीन में जो फर्क होता है उसको हमें सामने रखना पड़ेगा। उसके बगैर यह भसला हल नहीं हो सकता।

दूसरी बात आनेवारी के सिलसिले में है। जिसमें जिस सिलसिले में जो रेकमेंडेशन किया गया है उसका हम लिहाज नहीं कर सकते क्योंकि कानून के लिहाज से लैंड कमीशन जिस तरह का फैसला नहीं दे सकती। कानून में साफ साफ कहा गया है कि ब्लैक काटन, रेड, चल्का वेट लैंड अत्यादि के लिये आठ आने के ऊपर या नीचे की जमीन का अंक अलग अंकरेज तैयार करना पड़ेगा। जिस दृष्टि से जिस रिपोर्ट में लैंड कमीशन ने कानून को कान्ट्राव्हीन किया है। जो प्रोवीजन कानून में दिया है उसको गवारा नहीं किया जा सकता। प्रोवीजो में कहा गया है कि किसी अेरिया में जियादा आभदनी नहीं आती तो वहां अंकरेज बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यह नहीं दिया गया है कि आठ आने के ऊपर या नीचे के लिये कितना कम या ज्यादा करना चाहिये। जिसलिये जब तक जिस सेक्शन को अंमेंड नहीं किया जाता तब तक लैंड कमीशन ने जो सिफारिशें की हैं वह कानूनी तौर पर सही साबित नहीं हो सकतीं।

तर्ह तर्ह की साबिल्स को यहां लिमिट किया गया है। वेट लैंड के लिये अनुका कहना है कि आठ आने के नीचे की जमीन न रहे। कानून में कहा गया है कि आठ आने के ऊपर की जमीन छः अकड़ रहेगी और नीचे भी छः अकड़ रहेगी। दूसरी जगहों पर आपने ७ अकड़ और ८ अकड़ तक गुंजाअिश रखी है लेकिन सेक्शन ४ के तहत जिसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? सेक्शन ६ के तहत डबल क्राप के लिये ४ अकड़ रखेंगे और सिंगल क्राप के लिये ६ अकड़। लेकिन जिसके आगे बढ़ने के लिये सेक्शन ६ के तहत गुंजाअिश नहीं थी। लेकिन हुकूमत ने कहीं ६ अकड़ से सात अकड़ जिस तरह से लिमिट बढ़ाओ है, वह अलग बात है। ड्राय लैंड के बारे में इसी तरह से कम से कम तीन किस्में बनाना जरूरी था। आपने हर तालुके के लिये अवरेज कायम किया। लेकिन मैंने जित्तर तालुके की मिसाल देकर बताया कि जहां ४ आने अकड़ के हिसाब से असेसमेंट है वहां २४ अकड़ रखा और जहां डेढ़ रुपया है वहां के लिये भी २४ अकड़ रखा तो क्या जिससे नाअिन्साफी नहीं होगी? जिस लिहाज से आनेवारी को जो नजरअंदाज किया गया है वह नामुनासिब है। मैं मानता हूं कि १४, १२, ९, ८, ७, ५, ४, ३, और २ आने जिस तरह के असेसमेंट के लिये मुस्तलिफ किस्में शायद हम नहीं बना सकते। लेकिन कम से कम तीन किस्में अवरेज के हिसाब के लिये बनाये जा सकती हैं। मुल्क के वेस्टर्न हिस्सों में जो अवरेज पाया गया है वहां ११ आने प्रतवारी है और वहां २४ और ३६ अकड़ तय किया गया है। उसके ऊपर की आनेवारी के लिये अतना अिजाफा होगा और नीचे के लिये अतना होगा जिस तरह से हम रख सकते थे। जिसलिये असेसमेंट बेसिस को मैं अक बेहतरीन बेसिस समझता हूं। डेढ़ रुपये जिसका असेसमेंट है उसके लिये अगर २४ अकड़ रखा जाय तो उसके ऊपरवाली जमीन के लिये जो लिमिट होगी वह कम की जा सकती है। और कम होती है तो उसके लिहाज से जमीन की लिमिट बढ़ाओ जा सकती है। जिस तरह से अक लैंडर कायम करना चाहिये। लेकिन अगर अक लोकल अेरिया के अंदर मुस्तलिफ अेक्साम की जमीनात हों तो उन सब को अक ही लाठ से चलाने की आपने कोशिश की है। जिससे फायदा नहीं होगा। मेरा

सुझाव है कि अकरेज-कम-आनेवारी रखें। आनेवारी भी मेरी नजर से जरा काम्प्लीकेटेड है, जिसलिये मैंने पहले कहा कि असेसमेंट बेसिस रखा जाय। कानून बनते वक्त हम लोगों ने इस बात पर बहुत जोर दिया और रूलिंग पार्टी को अतिमीनान दिलाने की कोशिश की। लेकिन उस वक्त हम पर जिल्ज़ाभ लागाया गया कि आप अक्विटी नहीं करना चाहते, अलग अलग जमीन पर अलग अलग असेसमेंट होता है, जिसलिये क्लासिफिकेशन को ही बेसिस करार देना अच्छा है। उस वक्त आनेवारी पर जोर दिया गया और आज उसी को बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके भाने क्या हैं? अक वकील की तरह जब कोअी दलील आपके लिये फायदेमंद होती है तो आप उस पर जोर देते हैं और जब वहीं आपके खिलाफ जाती है तो कहते हैं कि उसमें कोअी कूबत नहीं है। अब कहा जाता है कि सिम्प्लीसिटी के लिये यह किया जा रहा है। उस वक्त जो प्रतवारी का द्रावा आप कर रहे थे वह अब कहां गया? मुझे भूलभारत के कर्ण को जो जबाब दिया गया था उसकी याद आ रही है। कर्ण से कहा गया कि उस वक्त तुम्हारा धर्म कहां गया जब कि अब संकट आने पर धर्म की बातें कर रहे हो? उसी तरह से मैं पूछना चाहता हूं कि कानून बनाते वक्त आपका धर्म कहां गया था? उस वक्त सिम्प्लीसिटी का आपका खियाल कहां गया था? क्या जिसका मतलब हम यह समझें कि उस वक्त आपको यह खियाल अिसलिये नहीं था चूंकि लैंडकमीशन मुकरर कर के कुछ लोगों को चंद लाख रुपये देना था या चंद डेप्युटी भिनिस्टर्स को बढ़ाना था? आज जब देखते हैं कि रेवीन्यू बेसिस के सिवा कोअी चारा नहीं है तो सिम्प्लीसिटी की दलील को हमारे भूत्ये थोपने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त मैं समझता हूं कि अेरिया असेससमेंट-कम-आनेवारी इसीको सब से अच्छा बेसिस समझते हैं। जैसे अक आनरेबल मेंबर ने कहा कि जमीन का रंग, क्लायमेट, जमीन की गहराअी, बारिश वगैरा सब चीजों का खयाल रखकर यह फैमली होर्लिंग और लोकल अेरियाज तय किये गये हैं। लैंड कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने से भालूम होता है कि वह सारी दुनिया घूमकर चूंकि वह गोल है इसलिये फिर से उसी नतीजे पर आ पहुंचे जिस पर हम लोग सिलेक्ट कमेटी में पहुंचे थे। लेकिन उस वक्त हम कह रहे थे तो उसको नहीं माना गया—पेज ६५, प्यारा १४७—

“We have actually reversed the process followed for determination of settlement rates and used the incidence of land revenue to find out the average type of soil for each taluka. The process is approximately correct and the results have been used only for the sake of comparison. Maximum rates are sanctioned for a standard soil (16 annas classification) in each group. The average assessment per acre for the group would, therefore, indicate the average soil value for that area. Such averages have been worked out wherever it was possible to do. Results are shown in Appendix 6.”

आखिर आनेवारी के बेसिस पर मुस्तलिफ अेरियाज में या तालुके में मैकजीमम और मिनिमम देखकर फायदा उठाने की कोशिश की। इसके साफ साफ माने यह है कि आनेवारी को ही बेसिस लेकर आप चल रहे थे। जिसमें कहा गया है कि मुस्तलिफ मुकामात पर मुस्तलिफ असेसमेंट होता है।

अगर ऐसा है तो जहाँ अंक से हालात हैं उनको लेकर चार या पांच ग्रुप बनाये जा सकते हैं। आज आपने जिस स्टेट के ८ हिस्से किये हैं। उसका असेसमेंट क्या है उसको देखकर लोकल प्रेरियांज कायम की और अंक कटिंग एक्सपेरिमेंट (Cutting experiment) के तौर पर वहाँ का अवरेज यील्ड (Average yield) निकाला। तालुके के अंदर कांटन, ज्वार, ग्राउंडनट, राबिस आदि का परसेंटेज कितना है उसको वर्कआउट कर के अवरेज आमदनी क्या होती है उसके लिहाज से १६ सौ के लिये कितना होता है उसको तय किया। और जिसलिये आपने हजारों मील का दौरा किया और अवेडीन्सेस लिये और पैसा खर्च किया। जिसके लिये जब हम यहाँ बैठकर यील्ड का मवाद दे रहे थे तो उसको लेने के लिये आप तैयार नहीं थे। ऑनरेबल मॅबर, लैंड कमिशन, मुझे माफ करें क्योंकि वह बहुत घूर कर देख रहे हैं। पेज ६८

“Results of crop experiments were made available to us. For the last 2-3 years, they have been obtained on random sampling method. Our intention was to verify or supplement this information through our enquiries. We had to adopt the only possible method of interrogation in spite of its obvious limitations.”

सिलेक्ट कमेटी में पांच पचास लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गयी थी और उनका भी कहना था कि लैंड रेवीन्यू को बेसिस करार दिया जाय। लेकिन लैंड कमिशन ने अब दूसरे तरीके से तय कर लिया है कि अितने अंकड में १६ सौ रुपये की आमदनी हो जाती है। मैं समझता हूँ जिसमें अंक बहुत बड़ी खामी है। आपने तालुके का अवरेज लिया है। लैंड कमिशन के सामने हमने अवेडीन्सेस दिये थे। उसमें यहाँ भाग की थी कि आप बहुत बड़े फार्म को मत लिजिये और बहुत छोटे फार्म को भी मत लिजिये, क्योंकि बहुत बड़े और बहुत छोटे फार्म के प्रतिशत उत्पादन में बहुत फर्क होगा। यह भी हमारा कहना नहीं कि साढ़े चार फॅमिली होल्डिंग को ही आप लिजिये। जहाँ अंक या दो फॅमिली होल्डिंगवाले किसान अपनी ज़िदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन पूरे तालुके का अवरेज लेकर उसमें पांच परसेंट का अजाफा किया गया। और यह कह कर किया गया कि ग्रेजिंग के लिये और झाड़ों के लिये जगह छोड़नी पड़ती है। लैंड कमिशन के मॅबरों ने कौनसे खेत में बैठकर किस झाड़ के फल खाकर यह पांच परसेंट को छोड़ा, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब हाउस में पचास परसेंट अक्सपेंडीचर आफ कल्टीवेशन हो, ऐसा कहा गया था उस वक़्त यह कहा गया कि ग्रेजिंग के लिये जमीन छोड़नी पड़ती है, तीन चार साल में अंकाध साल खराब फसल रहती है उसका लिहाज करके ५० फीसद छोड़ने का तय किया गया। मुझे उस किस्से का याद आ रहा है जब कि अंक बच्चा घी लेने के लिये दुकान पर गया तो अंक पैसे के घी के लिये दुकानदार ने ‘घीनो पैसा और पैसा नो घी’ ऐसा कहकर उससे दो पैसे वसूल किये। और आखिर तब बच्चा यह न समझ सका कि अंक पैसे के घी के लिये अरुने दो पैसे क्यों लिये ! उसी तरह से आज फॅमिली होल्डिंग तय करते वक़्त पांच परसेंट ग्रेजिंग के लिये छोड़ना चाहिये, जिसकी अहमियत सामने रखी जा रही है। लेकिन क्या इस तरह से यह छोड़ने की सचमूच जरूरत थी ? कहा जा सकता है कि वह मैकजीमम के लिये जरूरी है। लेकिन हमारा कहना है कि १६ सौ बहुत ज़ियादा होते हैं। अगर आप हमारे कहने के मुताबिक मैकजीमम करार देते तो वह ज्यादा से ज्यादा साढ़ेबारा सौ

तक जाता। उसको आपने कन्सिडर नहीं किया। इसलिये ५० परसेंट छोड़ने के बाद ग्रास अनिकम १६ सौ हो गया। इसलिये यह जो रखा गया है वह मुनासिब नहीं है।

फैमिली होल्डिंग फिक्स करते वक्त रेवीन्यू सर्कल को स्प्लिट अप करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिये लैटीटचूड दी गयी है। अगर कोई इसको रिपोर्ट आफ लैटीटचूड कहें तो गलत न होगा। हर जगह लैटीटचूडज दिये गये हैं और इसकी बिना पर पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट किया गया है। अंक रेवीन्यू सर्कल में अगर जमीन के दो हिस्से होते हैं तो वहां अंक ही फैमिली होल्डिंग फिक्स किया गया है चूंकि वहां रेवीन्यू सर्कल को स्प्लिट अप करना पड़ेगा। यह लैटीटचूड क्यों दिया गया यह मेरे समझ में नहीं आया। लेकिन इसकी वजह से वहां नुकसान होता है और फैमिली होल्डिंग बढ़ जाता है। इसलिये मेरा कहना है कि यहां जो रेवीन्यू सर्कल्स को स्प्लिट करने की जरूरत महसूस की जा रही है वह न करने की वजह से नाबिन्साफी हो रही है। मुझे यह रिपोर्ट आफ आबिट्रेशन मालूम होता है। लैंड कमीशन के मॅबर ने कहा कि जो लिमिट मुस्तलिफ साजिल्स के लिये रखी गयी है वह आबिट्ररी है। जैसे आठ आने की जमीन के मुकाबले में उसके नीचे की जमीन हो तो वह टू थर्ड रखी गयी है। उन्होंने कहा कि बेस्ट साजिल के लिये २१ अंक और वर्स्ट साजिल के लिये ६० अंक रखी गयी है। लेकिन इसके लिये बेसिस क्या है? उन्होंने यह सब आबिट्ररीली किया है इसलिये हमको भी आबिट्ररीली इसके बेसिस को ढूँढना पड़ रहा है। यहां चूंकि आठ मिनिस्टर्स हैं इसलिये इसके आठ हिस्से बनाये गये हैं। इसके सिवा और कोई बेसिस हो तो हमें बताया जाय। उन्होंने कहा कि पहले हिस्से में तीन का फर्क होना चाहिये। यह तीन का ही फर्क क्यों होना चाहिये? अंक चीफ मिनिस्टर है और दूसरा अनुके नजदीक जाना चाहता है इसलिये इसमें अतना कम फर्क रखा गया है और दूसरों के लिये ६-६ का फर्क रखा गया है। ये आठ ही हिस्से क्यों बनाये गये हैं? १६ जिले हैं? तो १६ हिस्से क्यों नहीं बनाये गये?

इसके बाद शुगरकेन के सिलसिले में यहां पर खास रियायत रखी गयी है। यह कहा जायगा कि इसके लिये ज्यादा खर्चा आता है इसलिये रियायत दी गयी। लेकिन इससे मैं कन्विन्स नहीं होता। इसीके लिये ज्यादा रियायत क्यों दी जा सकती है? रिपोर्ट में कहा गया है कि अंक अंक के अंदर १६ सौ का ग्रास अनिकम भी हो सकता है। मैंने वर्क आउट किया तो वह ४.७ तक आता है। इसके लिये चार अंक लेना और दूसरे क्राप निकालनेवालों के लिये भी चार अंक ही छोड़ना कहां तक मुनासिब है? लोग कहते हैं कि बड़े बड़े सरमायेदारों के आप हमी हैं, इसलिये शुगरकेन के बारे में आपके दिल में साफ्ट कार्नर है। मेरा ह्याल है कि शुगरकेन के लिये बहुत ज्यादा अेरियन छूटनेवाली है। जिस रिपोर्ट के सिलसिले में मुझे आखिर में अतना ही कहना है कि जो सेक्शन है उससे यह मुताबिकत नहीं रखता। कानून के सेक्शन्स को नजरअंदाज करके असेसमेंट को दूर रखते हुये लेकिन छिपे तौर पर उससे मोहब्बत करते हुये यह लिमिटेशन कायम किया गया है और अवरेज निकाला गया है। इसकी सिम्प्लीसिटी के लिहाज से इसकी ताअीद करने में मुझे बुजर नहीं है; लेकिन अक शर्त पर ही ताअीद में कर सकता हूं और यह है कि इससे अतनी डिस्पेरिटी पैदा न हो जिससे जैसे मैंने अंक तालुके की मिसाल आपके सामन रखते हुये बताया कि आनवारी के लिहाज से फैमिली होल्डिंग और अेरिया का ताअुन न हो बल्कि असेसमेंट के बेसिस पर हो। कन्नड के आनरेबल मॅबर ने कहा कि इसकी वजह से वकीलों को पैसा देना पड़ेगा। हर

देहात के अंदर हर काश्तकार को, अपना अपना सब्बे नंबर और उसका तहसील और वह क्या देता है वह मालूम रहता है। मतलब यह है कि सर्वेनंबर और तहसील से अवेरेज हम तय कर सकते हैं। अगर अके रुपया अकेड की जमीन है और वह बीस रुपये तहसील को देता है तो बीस अकेड जमीन है। चार आने की जमीन है और पांच रुपये तहसील को देता है तो बीस अकेड जमीन है जिस तरह से हिसाब निकाला जा सकता है। जिससे आप अक्वीटबल तरीके से तय कर सकते हैं।

अंक और चीज कहना चाहता हूं, वह है वेट लैंड के बारे में। जेरे बावली की जमीन किसान की मेहनत से होती है जिसलिये उस को भी ड्राय लैंड करार दिया जाना चाहिये; ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन वह सही मालूम नहीं होगा। तेलंगां के अंदर जेरेबावली काफी जमीन है। क्या उसके लिये मेहनत नहीं करनी पड़ती? मेरा ख्याल है कि जेरे बावली की जमीन वेट लैंड के तौर पर तसब्बूर की जानी चाहिये, कम से कम ड्राय के तहत तो तसब्बूर नहीं की जा सकती। मैं कहूंगा कि जेरेबावली की जमीनात को लाइजि अरिगेशन के बेसिस पर रखा जाय और ड्राय के लिये जितनी जमीन रखते हैं उसके निस्फ उसके लिये रखें। हमने तय किया है कि ड्राय लैंड के मुकाबले में वेट लैंड आधी रखी जाय।

जिसके बाद प्राजिसेस के बारे में कहा गया है। वह आधा गुना बढ़ गयी है, ऐसा मेरा ख्याल है। उन्होंने कहा कि पैडी की प्राजिसेस २५ परसेंट बढ़ी हुयी है और कैश प्राजिसेस कम नहीं हुयी है। जिस लिहाज से अगर जमीन बढ़ाई गयी है तो वह मुनासिब नहीं है। आम तौर पर यह कहा होता है? कुछ मुस्तलिफ मुकामात पर जहां फैमिली होल्डिंग कायम किया गया है वहां सेक्शन ४ के तहत जो सोचा गया था उसके लिहाज से डेढ़ गुना होता है और उसके लिहाज से सीलिंग भी बढ़नेवाला है। लैंड कमीशन की रिपोर्ट में किसी पेज पर बहस करते हुये उन्होंने कहा कि २४ के बदले ३० सीलिंग बनाया जाता है तो वह लैंड ओनर और टेनेन्ट दोनों के लिये या तो फायदेमंद होती है या नुकसानदेह होती है। लेकिन उन्होंने माना है कि सीलिंग के लिहाज से सीलिंग बढ़ता है। मैं समझता हूं कि जो फैमिली होल्डिंग मुस्तलिफ अेरियाज के लिये रखा गया है वह ज्यादा है। जिसकी वजह से जो सरप्लस लैंड मिलने की आशा थी और ऐसा जो वाइदा किया जा रहा था वह अब मिलने के अिमकानात नहीं हैं और दीगर तरीकों से भी जिसका असर बहुत बुरा होगा। और जिसके लये अेरिया असेसमेंट का रैंडर न लगाया जायेगा तो नुकसान होगा। जिन चंद चीजों को मैं हाजुस के सामने रखता हूं और अुमीद करता हूं कि हुकूमत उस पर गौर करेगी।

*\*Shri Phoolchand Gandhi (Omurga):* I think I have to speak in English this time. The report of the Land Commission and the report of the Select Committee are all in English. If you please excuse me, I will proceed further.

*Several hon. Members:* "Please speak in Hindi".

*Shri Phoolchand Gandhi:* Well, I do not mind.

स्पीकर सर, लैंड कमीशन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में अंक लब्ज भी अधर अधर न जाते हुये सिर्फ उन्होंने जो सफा दर सफा कहा है उसको सामने रखते हुये उस पर मैं अपने कमेंट्स

पेश करूंगा। पहला चैंप्टर डिस्ट्रिक्शन का है। उसके सफा दो पर पहले ही अन्होंने जो कुछ जिक्र किया है वह गवर्नमेंट के सक्क्यूलर के बारे में है। लैंड कमीशन के मॅबरान्स को यह अेहसास हुआ कि यह सक्क्यूलर कानून के मुगाथिर है, अैसा मालूम होता है। सफे २ के पैरा ६ में वे लिखते हैं:—

“We are informed that the operation of many important provisions of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act (as amended in 1954) which have a reference to family or basic holdings was automatically suspended till the determination of local areas and family holdings under sections 3 and 4 of the Act.”

हुकूमत ने जो सक्क्यूलर दरमियान में जारी किया वह अुनको पसंद नहीं है। लैंड कमीशन के मॅबर जो अेक वक्त यह राय रखते थे कि अिरैग्युलर असेसमेंट होने की वजह से अुसको फैमिली होल्डिंग तय करने के लिये बेसिस करार नहीं दिया जाना चाहिये, वह अुन्होंने लैंड कमीशन के मॅबर होने के नाते अुसके खिलाफ रिपोर्ट करने की कोशिश की है और यह बात अिस सफे में है। अुनकी राय देखने से मालूम होता है की अुनको यह सक्क्यूलर पसंद नहीं था।

“We do not at this stage intend to indulge in any discussion of the legal issues involved in or implications of such a suspension of some provisions of the Act.....”

यह कानून सही है या नहीं अिसके बारे में भी अुनको शुबहा मालूम होता है। अितना ही शुबहा जाहिर करने के लिय अिस सतर को डाल दिया है कि मुमकिन है कि अिस गरज के लिये यह सक्क्यूलर जारी किया गया। अब सक्क्यूलर को बंद किया गया है चूंकि फैमिली होल्डिंग तय किया

“.....to get first-hand local knowledge of the relevant factors viz., soils, climate, rainfall, methods of cultivation, crop patterns, yields, etc.”

गया है। चैंप्टर सात में अुन्होंने, दौरा किसलिये किया गया वह तफसील से बतलाया है। ये बहुत सी चीजें अिसमें से बगैर दौरे के मिल सकती थीं और बहुत सी चीजें दौरा करने के बाद भी नहीं मिली हैं।

अिसके बाद अब दूसरे चैंप्टर पर आता हूं। सफे १४ पर प्यारा ३८ है, लैंड कमिशन ने बिल्कुल अिक्कतद में ही अिस तरह से शुरू किया है मानों पहले से ही दिक्कतों का रोना शुरू किया है। अिस तरह से कोअी रिवर के बारे में कहा जाता है कोसी नदी जब कभी बाढ लाती है तो सब को खलाती है अुसी तरह अिस कमिशन ने भी शुरू में ही दिक्कतों का रोना रोया है।

पहले अुन्होंने चैंप्टर ३८ रखा है वह अिस तरह से है।

“The following extract from the latest United Nations publication on land reforms will show that all Asian countries have experienced similar difficulties in enforcing tenancy legislation and in controlling tenancy conditions.”

अिसमें अुन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि सभी अेशियायी देशों की टेनन्सी लेजेस्लेशन के बारे में



काफी डिफिकल्टीज आती हैं जिसके बाद आगे अन्होंने यह लिखा है की—

“As a result of the scarcity of farm land, its right of use is highly valued in terms of money and labour..... In these conditions, even the most comprehensive legislation to control conditions of tenancy may be ineffective.....”  
अनुका कहना यह है कि टेनन्सी के मसले पर इस तरह का यदि कोयी काँप्रीहेन्सिव्ह लेजिस्लेशन बनाया गया तो वह अनअफेक्टिव्ह होगा। और अन्होंने यह भी कहा है कि हमने जो रिपोर्ट दिया है वह भी बराबर नहीं होगा। अन्होंने पहले ही मान लिया है कि हमारा रिपोर्ट भी बराबर होगा ऐसी बात तूही है।

जिसके बाद इस रिपोर्ट के पेज १५ पर प्यारा ३९ और ४० हे अुसमें लैंड सेन्सेस का हवाला दिया गया है। और अुसमें लैंड सेन्सेस के इंप्लिकेशन को नजरअंदाज किया गया है लेकिन लैंड सेन्सेस के बारे में इस कानून के दफा ५३ के अलफाज मौजूद हैं। इसी में फॅमिली होल्डिंग और लोकल अेरिया के बारे में भी कहा गया है। और जबतक लैंड सेन्सेस पूरा नहीं होता तबतक फॅमिली होल्डिंग और अेरिया तय नहीं हो सकता है।

सेक्शन ५३ अे इस तरह से है—

“53—A. For the purposes of this Act generally and in particular for the administration of this chapter”.

सारे कानून में यह अेक अहम दफा है और यह साफ तौर पर कहा गया है कि इस चैप्टर के अॅडमिनिस्ट्रेशन की बहुत जरूरत है —इसी से हमें सरप्लस जमीन मिलने की अुमीद है।—आगे इसी में कहा गया है कि—

“The Government may take a census of land holdings and details of cultivation in the prescribed manner”.

इसी ५३ दफा के तहत स्टेट भर में १ साल से लैंड सेन्सेस काम शुरू हुआ है। लेकिन अभी तक सिर्फ अेक बटे तीन ही काम हो पाया है। मेरी समझ में नहीं आता कि जबतक लैंड सेन्सेस का काम पूरा नहीं होता तबतक कमिशन की रिपोर्ट बराबर कैसे हो सकती है? लैंड सेन्सेस का काम पूरा होने के लिये तो अभी कम से कम दो साल लगेंगे। लैंड सेन्सेस का काम जबतक पूरा नहीं होता है तबतक हम फॅमिली होल्डिंग तय नहीं कर सकते और जबतक फॅमिली होल्डिंग तय नहीं होता तबतक हमें सरप्लस लैंड कहां से मिलेगी? जब तक लैंड सेन्सेस नहीं होता और फॅमिली होल्डिंग तय नहीं होता तबतक हमें सरप्लस जमीन कैसे मिल सकेगी?

तो इस तरह से अितनी अुजलत से ४-६ महीनों में रिपोर्ट पेश कर के लैंड कमिशन क्या हासिल करनेवाली है, मेरी समझ में नहीं आता है। और इस तरह का रिपोर्ट क्या काम आनेवाला है?

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—बेदखलियां करने के काम आनेवाला है।

श्री. फूलचंद गांधी:—खैर इस चैप्टर के बाद पेज २१ पर प्यारा ५१ है। प्यारा ५१ जो है वह तो पूरा ही पढ़ने के काबिल है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जबकि लैंड कमिशन का अस्तित्व ही इस कानून के दफा ८४ के तहत है, यह कानून ही इस असेंबली में काफी डिफिकल्ट

होने के बाद पास हुआ है और इसके बाद अूस कानून के तहत लैंड कमिशन मुकरर होता है तो वह अिस कानून की खिलाफवर्जी किस तरह की जा सकती है ? अिस तरह की राय कैसे दे सकता है ? यह मेरी समझ में नहीं आता है। कानून की खिलाफवर्जी किस तरह की जाय, यह बताने के लिये कमिशन मुकरर नहीं किया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—वही ज्यादा मुनसफाना समझा गया होगा।

श्री. फूलचंद गांधी :—मैं नहीं समझता की अैसा समझना ठीक है। अिसके बाद प्यारा ५१ है।

“Para 51. . . . . The first condition, therefore, does not contain any definiteness. . . . .”

लैंड कमिशन ने दफा ४ की खिलाफवर्जी की है। फस्ट कंडिशन जो बतायी गयी है वह अिस तरह से है।

“does not contain any definiteness about the size of the holding except perhaps for the implied sense regarding the maximum area which a family would be able to cultivate or supervise. We have, therefore, to exclude the criterion of the plough or work unit and of personal cultivation by an average family of five.”

अिसमें अुन्होंने बताया है कि प्लो युनिट ( Plough unit ) या वर्क युनिट ( Work unit ) से जो और पर्सनल कल्टीवेशन ( Personal cultivation ) के अलफाज रखे गये हैं अुसे अेक्सक्लूड करने की शिफारीस करते हैं। प्लो युनिट और वर्क युनिट को नजरअंदाज करने के लिये कहा जा रहा है। मैं कहता हूं कि आप अेक बार प्लो युनिट ( Plough unit ) या वर्क युनिट ( Work unit ) को नजर अंदाज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल कल्टीवेशन को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है ? दफे चार खिलाफवर्जी करने के लिये वजूहात् पेश किये गये हैं। अिसका अुनको क्या अधिकार है।

अिसके बाद अब मैं सेक्शन २ प्यारा ४ में जो बताया गया है अुस पर आता हूं :

“We are also required to adopt the prices prevailing at the time of determination. In view of the fact we would therefore, be guided more by the conditions of the produce than the limits prescribed”

अेक बात प्रिसक्राइब करने के बाद भी अुसको बदलने की कोशिश की जा रही है। अिस तरह से करने के लिये अुन्हें क्या अेखत्यार है ?

“Limits can, we believe, be altered by involving the proviso to section 4.”

डूबते हुअे आदमीको तिनके का सहारा वैसे ही अिनकी गत है।

“The limits can, we believe, be altered by involving the proviso to section 4 or necessary even by an amendment of the Act”.

में यहां यह बात रखना चाहता हूं कि हमने असेंबली में बैठकर यह एक कानून बनाया। जिसमें काफी दिनों तक बहस होने के बाद हमने एक अहम दफा चार वह पास किया। और उसके सब सेक्शन १ और सब सेक्शन २ में प्रोविजो भी पास किया और उसके तहत कुछ रूल्स भी प्रिस्क्राइब किये, उसमें जो कुछ एक्सेप्शन्स ( Exceptions ) रखे गये थे अन्हे ही रूल्स बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह कैसे हो सकता है ? और यह भी कहा गया कि यह दफा काबिले अमल नहीं मालूम होता, लिहाजा लैंड कमिशन (Land Commission) ने अपनी राय दी है कि इसे अमैंड करना चाहिये। जब तक जिसमें अमैंडमेंट न किया जाय तबतक यह नाकाबिले अमल है। लेकिन इस तरह से जो दफा हमने बनाया है उसे अमैंड करने की शिफारिस करने का लैंड कमिशन को क्या अख्तियार है ? हमने जो अधिकार अुहीं दिये हैं अुन्हीं के तहत अुन्हे काम करना चाहिये।

अुसके बाद पेज २३ पर प्यारा ५६ जो है वह इस तरह से है—

“With different types of land, varying soil patterns, or climatic zones combined with sub-divisions and fragmentation of holdings a majority of holdings today presents a very complex picture. Small parcels of lands may in some exceptional cases exhibit uniformity of soil but there would be very few holdings which do not have a variety of soils. There can thus be an infinite number of combinations or permutations of varying kinds and classes of soils, and it is humanly impossible to attempt determination of family holdings for each such kind or class of soil”

मेरी समझ में नहीं आया कि यह कौनसी थीसिस है ( Thesis ) कि यह बात ह्यूमनली अपॉसिबल (Humanly Impossible) है। ह्यूमनली अपॉसिबल क्या हो सकता है ? ऐसी भी कोई बात है जो ह्यूमन चाहे और न हो सके। हर देहात में जाकर भी आप देख सकते थे कि वहां पर आठ आने के अपर कौनसी जमीन है और आठ आने के नीचे की कौनसी जमीन है। जिसमें आपको तो अच्छा होता और दो तीन साल तक यह लैंड कमिशन का काम चल सकता था। और दो तीन साल मजा लूटो है ही क्या बात ? और एक लंबी चौड़ी फेरिस्त बनाकर पेश की जा सकती है। जिससे कम से कम अनिजस्टीस होने के अिमकानात हैं जिससे फिर कोई कनफ्युजन होने का डर नहीं है। आज तक मजा लूटी, और थोड़ी और मजा लूटने को मिलती अुस में हर्जा ही क्या था ? अुसमें अनिजस्टीस तो कम होता। और आप हर एक क्लॉस की सॉजिल के लिये भी फॅमिली होल्डिंग तय कर सकते थे।

अुसके बाद चेप्टर ५७ का प्यारा २४ इस तरह से है—

“The confusion will be worst confounded when varying family holdings for different kinds and classes of lands and for different local areas are combined with varying operative multiples and fractions and with complex fragmented holdings. We do not, therefore, consider such a determi-

nation to be in the reach of practicability”.

आपने कहा है कि अिन तमाम बातों का लिहाज करना प्रॅक्टिकेबल ( Practicable ) नहीं है। प्रॅक्टिकल करनेवाले तो बहुत लोग हैं आप यदि काम से घबराते हैं और कहते हैं की जिसमें प्रॅक्टिकेबलीटी नहीं है तो वह आपकी कमजोरी है। यह प्रॅक्टिकल नहीं है, यह जो आपका ख्याल है वह गलत है अगर चाहे तो आदमी कर सकता है। लेकिन कष्ट उठाये कौन ?

असके बाद पेज २४ पर प्यारा ६० है। वह जिस तरह से है—असमें सिप्लिसिटी ( Simplicity ) के बारे में कहा गया है कि जियादा से जियादा सिप्लिसिटी होनी चाहिये। श्री. कृष्णमा-चारी जो प्लॅनिंग कमिशन के मेंबर हैं अन्होंने भी कहा था कि सिप्लिसिटी होनी चाहिये। जिस लिये असेसमेंट पर फॅमिली होल्डिंग तय करे तो अच्छा होगा। अब आप जरा प्यारा ६० जिसका जिकर किया है उसकी तरफ जरा मुलाहिजा फरमायें।

“Simplicity of formulas can be achieved by broad averages and by providing enough latitude for variations.”

यह कहा गया कि सिप्लिसिटी लाने के लिये ब्रॉड अवेरेजेस ( Broad Averages ) रखने चाहिये लेकिन मेरी समझ में नहीं; आया ब्रॉड अवेरेजेस का क्या मतलब है? क्या जो मनमाने निकाले जा सकते हैं वह ब्रॉड अवेरेजेस हैं? अगर ब्रॉड अवेरेजेस का यही मतलब है तो फिर उसके लिये जिस तरह से अेक कमिशन बनाने की और घूमने फिरने की क्या जरूरत थी? वह तो आप यहां पर ही टेबल पर बैठकर भी बना सकते थे। और अेक सिपलेस्ट फारम्युला बना सकते थे। लेकिन आपने वैसा नहीं किया।

असके बाद पेज ३६ और प्यारा ९३ आता है। जिसमें डिफरन्ट क्लॅसेस ऑफ सॉइल को फॅमिली होल्डिंग के तायुन करने में लिया जाना चाहिये या नहीं, असके बारे में कहा गया है—

“We are therefore, of the opinion that the family holdings need not be determined separately for both the types of soils in any given area.”

अनुका कहना है कि फॅमिली होल्डिंग का तायुन अेक ही जगह के अलग अलग जमीनात के लिये फॅमिली होल्डिंग का तायुन अलग अलग करना ठीक नहीं है। असके बाद आगे चलकर वे कहते हैं कि—

“Otherwise, we would be embarking upon an impracticable proposition of preparing village-wise lists of fields or portions of fields exclusively having Black or Red soil”.

जिमप्रॅक्टिबिलिटी का भूत बहुत जोरोसे सवार दिखता है। हर बात में जिमप्रॅक्टिबिलिटी ( Impracticability ) का सबाल लाया जाता है। मेरा कहना है कि अितनी जल्दबाजी करने की जरूरत ही क्या थी? जब आपको अेक अहम काम सौपा गया था तो उसे अितनी अुजलत से करने की कोशिश क्यों की गयी? चार महिने में ही यह काम होना चाहिये था, अैसी तो बात नहीं है। और भी कुछ दिन लगते या कुछ महिने भी लगते

तो क्या हर्ज था और ९ महीने में तो बच्चे की भी तो डिलिव्हरी होती है। तो ९ महीने में जरूर ही डिलिव्हरी हो जाती। जब हमें कुछ सरप्लस लैंड मिलने की उमीद है तो जरा जियादा कष्ट करते तो क्या होता था ? विलेजवाजीज लीस्ट भी बनानी पड़ती तो क्या होता ? विलेजवाजीज लीस्ट तो क्या लेकिन गिरदावर सर्कल भी तोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं, यह कैसे हो सकता है ? हर वक्त यह कहा जाता है कि यह अिमप्रैक्टिबल है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है। जिसके लिये अप रेविन्यू डिपार्टमेंट की मदद ले सकते थे। और दूसरे जो भी स्टैंडिस्टिक्स मौजूद हैं उनको मदद ले सकते थे। आज भी आपने जो यह रिपोर्ट पेश की है उसको डिलिव्हरी में भी आपने रेविन्यू ऑफिसर की मदद ली है तो दूसरे भी कामों में लेने में कोओ हर्ज नहीं था।

जिसके बाद पेज ३९ पर प्यारा ९६ है। वह जिस तरह से है।

“The classification table (given on page 38) thus shows that classification of wet lands in two categories, one with a soil value of 0-8-0 or more and another of remaining lands would not be correct as there would be practically no wet lands with soil value lower than 0-8-0.”

जिसमें एक क्लासिफिकेशन टेबल ( Classification table ) दिया गया है।

“Similarly classification of soils in western districts in two classes, the first, of lands with classification of 0-8-0 and above and the second, of remaining lands would also be a *grave mistake*, as majority of cultivated lands will thus fall in the first class”.

यह तो एक अजीब और गरीब हालत है ? जिस तरह से ग्रेव मिस्टेक ( Grave mistake ) करने का लैंड कमिशन को क्या अख्तियार है ? जिस तरह से मिस्टेक करने की उसकी क्या हिम्मत है ?

“Majority of cultivated land will never fall in the first class, perhaps it may be half class middle lower class may be more, higher class may be less.”

यह बिल्कुल गलत है।

“In our opinion the determination of family holdings with direct reference to soil classification will land us in more and more confusion.”

यह नुकतेनजर कमिशन का बिल्कुल गलत है जब कि कानून में एक डायरेक्टिव्ह ( Directive ) दिया गया है तो क्लासिफिकेशन ( Classification ) को कैसे नजर अंदाज किया जा सकता है ?

confusion worst confounded and impracticable.

यह अलफाज सारे रिपोर्ट में यहां वहाँ फेंक दिये गये हैं और सब पूरे रिपोर्ट में असे बिखरा गया है। और जो आरग्युमेंट्स किये गये हैं वह सब कानून की खिलाफ वर्जी कैसे की जाय अिसके बारे में ही किये गये हैं।

अिसके बाद सफा ४० पर मैं दरमियान में पढ़ रहा हूँ।

“If we decide to adopt soil classification as the criterion for applying various sizes of family holdings, we will have to prepare village-wise lists of fields having different soil values or even if we make only two categories in section 4, we will have to prepare village-wise lists of 1st class and other lands separately for Wet, Black-cotton, and Chalka lands.”

पहले जैसे ही आरग्युमेंट्स यहां भी पेश किये जा रहे हैं। औसी खिलाफ वर्जी करने का कमिशन को क्या बेखतियार है, यह मैं पूछना चाहता हूँ। आपको दफा ४ का अमल करने के लिये कहा गया था। आपको जिस कानून की पाबंदी करने के लिये कहा गया था, आपको जिस कानून की पाबंदी करने के लिये कहा गया है वह तो आपको करना ही चाहिये।

“We will have to do it. We have not created by this Act law-breakers, we have created law-abiders. We expect them to abide by the law and they should not violate it.”

अिसके बाद जो कहा गया है उसको तो पढ़ने के लिये भी मैं हिचकिचाता हूँ।

“We shudder to think”—I am really shivering to read these lines.

“...of these requirements with reference to the complex nature of the peasant's holdings and the need of elaborate calculations for reducing different parts of holdings in terms of a standard of unit adopted for conversions.”

अुसी पेज पर आगे प्यारा ९९ है जो अिस तरह से है —

“Adopting the two classes of soils for determination of family holdings as it is conceived in the Act, is also difficult because no statistics are available for reference to such classification of soils.”

आपने अेक ढांचा यहां पर पेश किया है। लेकिन अुससे आपको क्या मिला है? लैन्ड कमिशन ने अेक प्यारे में लिखा है कि लैन्ड रेविन्यू मौजूद दिखाने अिस लिये जो हमने जो सर्वे रेकार्ड्स देखे हैं अुनसे यह मुनासिब समझा कि लैन्ड रेविन्यू को बेसिस बनाया जाय। जब सिलेक्ट कमिटी में अिसके बारे में बहस हो रही थी तब पर अेकर अिल्ड ( Per acre yield ) आबुट टन आदि के फिगर्स अुन्हें मिल सके तो आपको क्यों नहीं मिल सके? अुसमें दुश्वारी ही क्या थी?

“It would, therefore, be necessary to arbitrarily fix the relation which would perhaps exist between per acre yields of first class soils and per acre yields of other soils”.

असके बाद आपको आनावारी फिक्स करने के लिये मुश्किल ही क्या थी ? मैं कह सकता हूँ कि जैसे भी फीक्स करने में कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस तरह थियरी ऑफ ऑरबेट्री फार्जिडिंग (Theory of arbitrary finding) की जरूरत नहीं थी और थियरी ऑफ एवरेज फार्जिडिंग ( Theory of average finding ) की भी जरूरत नहीं थी। दफा ४ में मुद्देबिन किया गया है कि क्या करना चाहिये। लेकिन आपने उसे ओवर रूल ( Over rule ) किया जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। ऑरबिट्री फार्जिडिंग का मसला यहीं खतम नहीं हुआ। उन्होंने उसे हर जगह दोहराया है। मैं नहीं पता कि जिस थियरी ऑफ ऑरबेट्री फार्जिडिंग ( Arbitrary finding ) से क्या लाभ हुआ ?

प्यारा ४१ सफे १०१ पर जिसकी ही बहस की गयी है।

*The Chief Minister (Shri B. Rama Krishna Rao) :* For my clarification, I would like to know, Sir, whether the discussion today is on the notification issued by the Government or whether it is para-to-para discussion on the report of the Land Commission. So far as I understand, the discussion is on the notification issued by the Government; and I do not think any hon. Member is entitled to take the time of the House by making a running commentary on each passage contained in the Report. This is my impression. I want a clarification from you, Sir. I do not want to interfere with my friend; he can have as much say as he likes. I think and my impression is that the discussion today is on the notification issued by the Government and it is not given to any hon. Member to ridicule the Commission's report or to make remarks in a most discourteous manner as is being done by the hon. Member.

*Shri Phoolchand Gandhi:* I will clarify the point raised by the hon. Chief Minister. It is said that the discussion will take place both on the Land Commission Report as well as on the notification issued. I will read out that notification issued by the Government.

*Shri B. Rama Krishna Rao:* Not so, Sir. I am referring to the directive given by the hon. Speaker the other day when he fixed the date for discussion. If I am correct, he has made it clear that the discussion would be limited to

the notification issued by the Government regarding the family holdings. The discussion cannot go beyond the limits fixed by hon. the Speaker and no hon. Member can have the liberty of giving a sort of a running commentary as on a cricket match or some such other thing.

*Shri Phoolchand Gandhi:* The hon. Chief Minister need not worry about this matter. I am referring to his own notification No. 510. It is stated therein that the Hyderabad Legislative Assembly will discuss the recommendations of the Hyderabad Land Commission and the orders passed by the Government of Hyderabad in respect of local areas and family holdings in their notification. I take that both the notification as well as the report of the Land Commission are under discussion now and there is nothing wrong in discussing the two. The discussion so far had taken place touching the Land Commission Report. If I should be precluded from discussing the said Report, I do confine myself to the notification and do not deal with the Report. The notification is based on the Land Commission Report itself and it is impossible not to refer to it even while confining myself to the notification. But still, if the hon. Speaker gives a ruling in this respect that only the notification should be discussed, I will stick to that alone.

*Mr. Deputy Speaker:* I think the hon. member will finish his speech in 5 minutes.

*Shri Phoolchand Gandhi:* I request the hon. Speaker to be kind enough to give me 10 minutes more.....

*Mr. Deputy Speaker:* I am afraid to other members also will demand likewise. I cannot give, there is no time.

*Shri Phoolchand Gandhi:* I will solve the problem by finishing it within ten minutes.

अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता सिर्फ रनिंग कॉमेंट्री के तौर पर पढ़ता जाता हूँ ।

I will go on with the running commentary.

पेज ४१ प्यारा १०१ है —

“Rationalization” is used herein and I want to show in what context it is used.

रेशनलाइजेशन और सिप्लिसिटी अके जगह नहीं बैठती है ।



“We do not think that by deducing such averages we would be abandoning any rational approach to the problem. If it were necessary, we would have certainly sacrificed a little rationality for the sake of simplicity of operation of the reforms. But where rationalization is impossible and where some important factors have to be determined arbitrarily, it is certainly so far to have broad averages and achieve maximum simplicity rather than create confusion.”

रेशनलाइजेशन, सिप्लिसिटी का कनफ्युजन ( Confusion ) पैदा किया गया है। सिर्फ सिप्लिसिटी लाने के लिये ऑरबीटरी ( Arbitrary ) रखा गया है यहां तक सही है। इसके बाद सफा ७४ पर लिखा है—

Considering the obvious limitations of our enquiries and then to keep the number of grades as low as possible, we decided that the steps should be of six acres for each fall in the grade excepting the first step which should be of 3 acres only”.

Why did you decide this? What is the rational basis behind this? Perhaps you do not touch rational basis

इसके बाद ७५ सफे पर १६७वे पैरे में—

“.....We could not split up some such talukas because the two differing parts could not be separated without splitting the Revenue Circles.....”

We are aware of similar differences existing in some parts of few other talukas which have not been split up. Kandhar, Gangakhed and Georai for example have both the extreme types of soils, deep Black Cotton in the south towards the banks of Godavari and light Black or Red towards the north. We could not split up some such talukas because the two differing parts could not be separated without splitting the Revenue Circles.....”

एक अहम पेचीदगी पैदा हुई, रेविन्यू सर्कल को स्प्लिट अप करने की। तो जिसमें कानून की कितनी खिलाफवर्जी है! जमीन चाहे पत्थर की हो, चाहे रेड हो, ब्लैक काटन हो, चाहे सेकंड क्लास हो, सब के लिये एक नियम लागू किया गया। रेविन्यू सर्कल्स अंसी कौनसी सीतामाझी की लकीर है जिसको तोड़ने से मुश्किल पैदा हो सकती है!

जिसके बाद हाबुस का ज्यादा समय जिस पर न लेते हुअे जिस रिपोर्ट में जो दो डिस्सेंटिंग नोटस हैं  
अनुकी तरफ जाऊंगा। आनरेबल श्री के. व्ही. नारायण रेड्डी लिखते हैं कि—

“At the outset, I would like to point out that the Land Commission concerned itself unnecessarily with the preparation of an elaborate report on sections 3 and 4 of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, when the Commission had very little time at their disposal to make a comprehensive survey of the State and had no accurate and reliable agricultural statistics to enable them to come to proper conclusions in respect of these intricate issues. All the evidence that the Commission could gather had, to my mind, merely served to confirm their own fears regarding the futility of making recommendations within the framework of the aforesaid sections. The Commission in paras 51 and 52 of its report had specially referred to the need for a reconsideration of this particular section laying down limits for the Famil Holdings because of certain inherent defects which had come to light as a result of the investigation.”

जैसा कि मैंने कहा अपवाद का सहारा नहीं लिया जा सकता और नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक सतर अन्होंने बहुत मोके की कही है कि—

“I differ from my colleagues on the Commission in so far as they suggest that the proviso may be invoked for working the section, as they themselves have conceded that the reconsideration of the section was vital to its workability. Here I should say that all the decisions taken by the Land Commission have not been unanimous.”

मैं ज्यादा दोहराना नहीं चाहता लेकिन अतना कहना चाहता हूँ कि लेजिस्लेटिव्ह असेंबली के तीन मेंबर्स लैंड कमिशन में चुनकर आये हैं। उनमें से सिर्फ एक ही मेंबर जिस कमिशन की रिपोर्ट से मुत्तफिक हुआ पाया गया। दो मेंबर्स जिससे मुत्तफिक नहीं हैं क्योंकि अन्होंने भी अपने नोटस आफ डिस्सेंट लिखे हैं। यह कह देने के बाद नोटीफिकेशन के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि उसका बहुतसा हिस्सा जिसमें आ गया और मैं उसकी खामिया इसके पहले पेश कर दी हैं। और वह अखबारात में भी शायी हो चुकी हैं। लेकिन अतना हीपेश करना चाहता हूँ कि—

Any how this notification No. 51, dated 2nd August, 1954 is illegal and *ultra vires* of the powers of Government. It is against the spirit of the Act. The decision is hasty and arbitrary. No Land Commission was necessary to come to such a decision.

मैं हुकूमत से अदब से अस्तदुआ करूंगा कि किसी फॉल्स प्रेस्टिज पर न जाविये। जैसा कि लैंड कमिशन के मेंबर्स ने महसूस किया है. दफा चार को किसी सरत में तबदील करना सख्ती है। अगला

دفا چار کو پاबंद करना ही मकसूद है तो पाबंद कीजिये, लेकिन अितनी अजलत से जो नोटीफिकेशन आपने शायद किया है और लैंड कमिशन की रिपोर्ट को कबूल किया और मंजूर फरमाया है तो वह न फरमाविये। उसको अभी भी विथड्रा कीजिये और दफा ४ की पाबंदी करने की कोशिश कर के उसके बाद होल्डिंग तय कीजिये। अभी फैमिली होल्डिंग का अमल नहीं हो रहा है। मैंने जो कुछ कामेन्ट्री की है वह इसमें कुछ सुधार हो, इसलिये पेश की है। हमने जो कानून बनाया उसकी खिलाफवर्जी हम ही न करें, इसलिये यह नुक्ताचीनी की है। मैं हुक्मत से कहूंगा कि बरायेकरम इस नोटीफिकेशन को वापस ले और लेजिस्लेचर को अप्रोच हो कर दफा चार को इस तरह से बदला जाय जिससे यह रिपोर्ट इसमें ठीक तरह से बैठ सके और बाद में इस रिपोर्ट को कबूल करने की कोशिश करें।

The House then adjourned for recess till Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

The House reassembled after recess at Thirty Five Minutes Past Five of the Clock.

[Shri B. D. Deshmukh (Chairman) in the Chair]

\* श्री जी - गोपाल दाऊ (पाकहाल) :- मस्टर اسپेकरसर - आयुन के सामने जो नोटीफिकेशन ( Notification ) बघ के लै आया है अस में फैमिली होल्डिंग का डकर किया गया है - अस फैमिली होल्डिंग में लिन्ड कमिशन के म्बरस ने ( १०१ ) म्खतलफ म्कामात का दोहर के ( १३९ ) तल्लुन का दोहर करने के बल अपनी रिपुर्ठ पेश की है - थिन्सि अक्ठ का जो अहम स्कशन है ओस्के तल फैमिली होल्डिंग डक्लिर ( Declare ) की ग्ठी है ओर ओस्के डक्लिर क्ठे हुं फैमिली होल्डिंग को गुरन्मन्ठ ने तल्लिम कर के नोटीफिकेशन जारी किया है - जो गुर तल्ल है - अस में स्कशन २ की तल्ल वरुी की ग्ठी है या न्हीं अस पर गुर करना है - म्झे आयुन से ये एरुश करना है के ये जो फैमिली होल्डिंग म्कर की ग्ठी है आया वे ह्कि त रक्ती है या न्हीं - अस में आंठ अस्म तल्लै ग्ठे हैं - २१ अकर से लकर २० अकर तक र्मिन के अस्म तल्लै ग्ठे हैं - अस रिपुर्ठ से तल्ल है के आरिब्ररी ( Arbitrary ) तल्लि से ह्साब लगाया गया है - अस तल्लि में कोठी लिस ( Basis ) न्हीं तल्लै ग्ठी है - स्कशन २ के तल्ल तलाया गया है के क्लासिफिकेशन ( Classification ) हुना जरुरी है - अ तल्लिलत से म्तल्ल म्झे मरिद एरुश करना न्हीं है लिकन जो चिज म्झे तल्ल तल्ल पर एरुश करनी है वे ये है के लिन्ड कमिशन के म्बरुन ने अस तल्ल की कोशिश की है के ज्हां तक म्मकन हुंस्के र्मिनत अण लुगुन के हातह में रक्ठना चल्है जो बुरे बुरे र्मिनदार हैं - स स से बुरी गलुी जो लिन्ड कमिशन ने की है ओर जस्को गुरन्मन्ठ ने म्णुवर किया है वे ये है के र्मि बावुली र्मिनत अस में ढल्ल न्हीं हुंस्के बल्के अंको तल्लि में शल्ल

کیا گیا ہے۔ سکشن ۴ کے سب سکشن ۱ و ۲ میں بتایا گیا ہے کہ ۱۶ سو آمدنی کے لئے کتنی زمین کی ضرورت ہے۔ اس میں خشکی زمینات کو چھوڑنے کے لئے کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایوان سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حیدرآباد اسٹیٹ میں جملہ ۶ لاکھ ایکڑ زمین زیر باؤلی کاشت ہو رہی ہے۔ فیملی ہولڈنگ میں اسکو کنورٹ (Convert) کیا جائے تو (۶۶) ہزار فیملی ہولڈنگ ہوتے ہیں۔ اسکو لینڈ کمیشن نے (۶۶) فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا ہے اور لینڈ ریفرمس کا جو مقصد تھا اسکو اسطرح نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ مقصد کو چھوڑ کر من مانے طریقے پر عمل کیا گیا ہے۔ اور گورنمنٹ نے اسکو مان لیا ہے۔ حالانکہ موور آف دی بل نے صاف صاف طور پر کہا تھا کہ جن جن مقامات پر اچھی زمینات ہونگی اور جن جن مقامات پر خراب زمینات ہونگی اونکو چھوڑ دیا جائیگا۔ لیکن اب زیر باؤلی زمینات کو جنکا تعلق رنٹ کے سلسلہ میں خشکی سے تھا اب تری میں شریک کرنے کو مان لیا گیا ہے۔ کسی طرح لینڈ ہولڈر کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ رنٹ کے تعلق سے تصور کرتے ہیں کہ تری زمینات کا اسسمنٹ مقرر کیا جائے۔ جب فیملی ہولڈنگ کے تعین کا وقت آتا ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہاں زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ آٹھ سو روپیہ آمدنی کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچہ ہوتا ہے یہ زیر باؤلی زمینات کے لئے کافی نہیں ہے تو ایک ہزار دو ہزار یا زیادہ رکھ سکتے تھے۔ یہ کوئی تجارتی اصول نہیں ہے کہ آٹھ سو روپیہ آمدنی کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچ کریں۔ دو ہزار بھی رکھتے تو ہمیں عذر نہیں تھا۔ وہاں کے چھ ممبر ہیں اور ریونیو بورڈ کے ایک ممبر ہیں جو زمینات کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں ایوان کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو روپیہ خالص منافع حاصل کرنے کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچہ ہوتا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے۔ زیر باؤلی زمینات کا خشکی میں عمل کر کے فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا جائے تو میں پوچھتا ہوں کہ جو خشکی زمینات ہوتی ہیں انکا انکم کیا ہوتا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت جو ٹ انکم بتائی گئی ہے وہ آٹھ سو روپیہ ہے اور خالص منافع کے لئے آٹھ سو روپیہ خرچ بتایا گیا ہے۔ اور آٹھ سو روپیہ آمدنی کو فیملی ہولڈنگ سمجھا گیا ہے۔ اس میں تری زمینات کے لئے کوئی استثنا نہیں بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر پوری تری زمینات کو فیملی ہولڈنگ میں کنورٹ کیا جائے تو ۳۶ ایکڑ یا ۴۸ ایکڑ تری زمین آتی ہے اسکی (۹۶۰) روپیہ انکم ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ باؤلیاں نہیں کھدوائی جائیں گی۔ (Fertility) فرٹیلیٹی) آئندہ کم ہو جائے یا بڑھ جائے۔ جب ایک مرتبہ تعین کر رہے ہیں تو صاف طور پر یہ آنا چاہئے تھا کہ یہاں اتنی لمٹ ہے۔ آئندہ چل کر اس طرح کی لمٹ ہم کرتے تو پراڈکشن بڑھنے کا امکان تھا۔ اسی طرح (۴۸) ایکڑ زیر باؤلی زمینات کے متعلق لینڈ کمیشن اور حکومت نے مان لیا ہے اور پچھلے ڈسکشن میں بھی یہ چیز آچکی ہے کہ اس میں کافی خرچہ ہوتا ہے۔ (۶۰) ایکڑ آپ تری زمینات چھوڑ دینگے تو کیا انوسٹ کر سکتا ہے۔ اگر پیداوار میں اضافہ کرنا ہو تو لازمی ہوگا ایسی زمینات کو کم

کیا جائے۔ ایک طریقہ پر یہ بھی صاف طور پر کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں پراجکٹ ایریاز ہیں پانی زیادہ ہے وہاں (۶) ایکڑ اراضی کافی ہوگی۔ اگر فرٹیلیٹی اچھی ہو تو یہ زمین کافی ہوگی لیکن وہاں ریگڑ زمین۔ چلکہ زمین۔ ریڈ سوائل۔ بلاک کائن سوائل کے متعلق نہیں کہا گیا۔ پراجکٹ ایریا کے متعلق اینڈ کمیشن نے مان لیا ہے اور اوسکی سفارشات کو بھی گورنمنٹ نے اندھا دھند طریقہ پر مان لیا ہے۔ وہاں (۸) سو کی نٹ انکم ہو جاتی لیکن جہاں دوسرے زمینات ہیں وہاں فرٹیلیٹی اچھی ہی کیوں نہ ہو اس کے متعلق گورنمنٹ کہنا چاہتی ہے کہ اس میں بھی آٹھ سو روپہ آتے ہیں یہ کونسا طریقہ اور اصول ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آٹھ گریڈڈ سسٹم بنائے گئے ہیں اس کے متعلق میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اچم پیٹھ تعلقہ میں (۶۰) ایکڑ فیملی ہولڈنگ مقرر کی گئی اوسکے مقابلہ میں مدھرہ میں (۳۰) ایکڑ مقرر کی گئی۔ مدھرہ میں بلاک کائن سوائل ہے اور اچم پیٹھ میں چاکہ زمین ہے۔ وہاں (۶۰) ایکڑ میں آٹھ سو کی نٹ انکم ہوتی ہے اور سولہ سو روپہ گراس انکم۔ یہاں (۳۰) ایکڑ میں آٹھ سو کی نٹ انکم ہوتی اور سولہ سو کی گراس انکم۔ اچم پیٹھ میں فی ایکڑ ایک من پیداوار ہے تو مدھرہ میں دو من فی ایکڑ پیداوار ہونا لازمی ہے۔ چلکہ اور بلاک کائن سوائل کا تناسب دیکھا جائے تو زمین چار گونا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو لینڈ کمیشن کے ممبر اور حکومت دونوں بھول گئے۔ لینڈ کمیشن کی رپورٹ کے صفحہ (۳۲) پر یہ کہا گیا ہے کہ

“In various sections of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, the words ‘area of the family hold-in,’ wherever they occur have been used in a singular form with reference to each local area. It would therefore appear that the drafters of the bill perhaps thought that there would be only one size of family holding fixed for a local area.”

اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ رپورٹ ڈرافٹ کئے ہیں گویا وہ اس ہاؤس کے ممبر نہیں تھے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آنریبل ممبرس سے کہ کیا لینڈ کمیشن کے ممبر اس ایوان کے ممبر نہیں تھے۔ کیا انہوں نے اس ایوان کا مقصد نہیں سمجھا تھا۔ گویا انہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ڈرافٹ کرنے والے دوسرے تھے ہم نہیں تھے۔ فیملی ہولڈنگ کے سلسلہ میں اس ایوان کا مقصد کیا تھا اور اپنی لینڈ پالیسی کیا تھی اس کو نظر انداز کیا گیا اور آریٹری طور پر رپورٹ پیش کی گئی۔ اس کا صرف یہی ایک مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جو لینڈ پہلے سے زمینداروں کے ہاتھ میں ہے ویسے ہی رہنے دی جائے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ چلکہ کے مقابلہ میں ریگڑ زمین میں دو گنی ایلڈنگ (Yielding) ہو سکتی ہے بلکہ تین چار گونا ایلڈنگ ہو سکتی ہے۔ میں آنریبل ممبرس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس ایریا میں وہ تشریف لے گئے تھے کیا وہاں انہوں نے اچھی طرح جانچ کی۔ کیا وہاں کی

فرٹیلیٹی اور پیداوار کا انہوں نے معائنہ کیا۔ کراپ کٹنگ ایکسپریمنٹ لیوی کے زمانہ میں تیار کیا گیا تھا اور جس کو تیار کرنے کی ذمہ داری پٹیل پٹواریوں پر ہی ہوتی ہے جس پر سبھی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جھوٹ لکھتے ہیں سچ لکھتے ہیں۔ سب کچھ اونہی پر منحصر رہتا ہے۔ لیکن آنریبل ممبرس نے اس امر کی زحمت گوارا نہیں فرمائی بطور خود جاکر دریافت کرتے۔ اور عملی تجربہ کی بناء پر نتیجہ نکالتے۔ ہوسکتا ہے کہ کوئی کاشتکار اپنی زمین کی پیداوار کم بتلائے۔ کوئی کاشتکار اضافہ بتلائے۔ کیا آنریبل ممبرس یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے فلاں فلاں سرکل یا حلقہ سے پیداوار کے متعلق اعداد و شمار حاصل کیا اور نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ یہ اوس رپورٹ میں نہیں بتلایا گیا۔ جو رپورٹ ہمارے سامنے آئی ہے اوس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آر بیٹری طور پر ایوریج نکالا گیا ہے۔ ایک سمپل ایوریج پر اس کو رکھا گیا ہے۔ قیمتوں کا جو تعین کیا گیا اوس سلسلہ میں میرا عرض کرنا یہ ہے کہ مارکٹ ویالو جو لگائی گئی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ رین کے سلسلہ میں تو (۵۰) سالہ ایوریج لیا گیا ہے لیکن ریش کے سلسلہ میں ۵ سالہ ایوریج لیا گیا ہے۔ اگر اتنا ہی ایوریج ریش کے لئے بھی لگایا جاتا تو فیملی ہولڈنگ از خود کم ہو جاتی۔ اس میں شک نہیں کہ مارکٹ ویالو بھی قریب قریب وہی ہے لیکن دو سالہ پہلے کا ایوریج لیا گیا ہے۔ اس سکشن کے اندر مارکٹ پرائس جو رکھی گئی ہے اس حد تک کہاں پابندی کی گئی۔ یہ محض آپ نے اس وجہ سے رکھا ہے کہ ریٹ زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے فیملی ہولڈنگ از خود کم ہو جاتی۔ لینڈ کا ایریا کم ہو جاتا اور لازماً زمینداروں کو نقصان ہو جاتا اون زمینداروں کو بچانے کے لئے آپ نے یہ کیا ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کا پورا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس زمینات ہیں وہ اون ہی کے پاس رہنے دی جائیں۔ مرہٹواڑہ کے لئے ۲۱ تا ۳۰ ایکر تک بتلایا گیا ہے۔ ۳۰ ایکر کا جو حساب لگایا گیا ہے تو (۱۲۵) ایکر میگزیم فیملی ہولڈنگ ہوسکتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ مرہٹواڑہ میں (۱۲۵) ایکر اراضی رکھنے والے کاشتکار کتنے ہیں۔ آنریبل ممبرس کو یہ معلوم ہے کہ (۱۲۰) ایکر سے زیادہ اراضی رکھنے والے کاشتکار مرہٹواڑہ میں کم ہیں جن کے پاس سے ریزمپشن نہیں کیا جاسکتا۔ یہ نقطہ نظر ہم نے اس رپورٹ میں پایا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر ہوسکتا ہے کہ آنریبل ممبرس نے کافی جدوجہد کی ہوگی۔ کافی چھان بین کی ہوگی۔ رپورٹ کے اندر جو چیز انہوں نے رکھی ہے آخر اوس کے بیس کیا ہیں۔ وہاں (۸) سو روپیہ کی جو ایلڈنگ بتلائی گئی ہے اوس کے کیا بیس ہیں۔ گریڈڈ سسٹم کا کیا طریقہ ہے۔ پانچ تا چھ ایکر کا ڈفرنس بتلایا گیا ہے لیکن کس وجہ سے یہ ڈفرنس قائم کیا گیا نہیں بتلایا گیا۔ ۳۰ تا ۳۶ ایکر میں (۸) سو روپیہ آمدنی ہوسکتی ہے لیکن یہ چھ ایکر کا جو تناسب رکھا گیا ہے وہ کیوں رکھا گیا ہے رپورٹ میں نہیں ہے۔ گورنمنٹ کے نوٹیفیکیشن دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ لینڈ کمیشن نے جتنی چیزیں رکھی ہیں اون کا انحصار بارش پر رکھا گیا ہے۔ آنہ واری بیس نہیں لیا گیا۔ میں معزز ایوان کے سامنے دو چیزیں رکھوں گا۔ کوا کرتی کی آنہ واری چار آنے تین پائی ہے۔ اچم پٹھ کی

پانچ آنے آٹھ پائی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے اچم پیٹھ میں کلو کرتی کے مقابلہ میں کم رقبہ ہونا چاہئیے۔ اور بارش کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اچم پیٹھ میں زیادہ بارش ہوتی ہے اور کلو کرتی میں کم ہوتی ہے۔ وہاں بارش اور آنہ واری دونوں میں فرق ہے۔ اس لئے اچم پیٹھ میں کم رقبہ ہونا چاہئیے۔ لیکن رپورٹ کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اچم پیٹھ میں زیادہ رقبہ بتلایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ زیادہ تر بارش کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے جو مثال دی ہے اوس کے دیکھنے کے بعد یہ یسٹ ثابت نہیں ہوتا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو رقبہ ڈیکلیر کیا گیا وہ من مانے طور پر کبا گیا۔ جو چھان بین کی گئی ہے پہلے سے دماغوں میں اوس کا نقشہ موجود تھا۔ اور اوس کی تکمیل ہی کی خاطر یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ اوس کے انوسٹیگیشن کا جو طریقہ مقرر کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

\* شری ادھو راؤ پٹیل ( عثمان آباد - عام ) :- لینڈ ٹینسی ایکٹ کے تحت جو کمیشن مقرر ہوا تھا اوس کمیشن کی رپورٹ ہمارے سامنے آگئی ہے۔ اس سلسلہ میں مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایکٹ کے سکشن ( ۴ ) کے تحت جو پابندیاں کمیشن پر عائد کی گئی تھیں یا جو پاورس اوس کو دئے گئے اون پابندیوں اور پاورس سے کمیشن نے تو تجاوز نہیں کیا یہ سوال بہت اہم ہے۔ جب کورٹ میں یہ چیز جائیگی تو گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن کے ذریعہ جو فیملی ہولڈنگ مقرر کی ہے اوس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ میں سکشن (۴) ہاؤس کے سامنے رکھ کر یہ بتانے کی کوشش کرونگا کہ خود کمیشن کو اس کے متعلق شک و شبہ تھا کہ فیملی ہولڈنگ مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ آیا اس سکشن کے تحت آئیگا یا نہیں۔ میں ایک کوٹیشن پڑھ کر ہاؤس کو کنونس کرنے کی کوشش کرونگا۔ سکشن (۴) یہ ہے۔

“4. (1) Subject to and in accordance with the provisions of this section the Government shall determine in the manner prescribed for all or any class of land in any local area the area of a family holding which a family of five persons including the agriculturist himself, cultivates personally according to local conditions and practices and with such assistance as is customary in agricultural operations and which area, will yield annually a produce the value of which, after deducting fifty per cent., therefrom as cost of cultivation, is Rs. 800 according to the price levels prevailing at the time of determination.”

اس پر ہم نے اوس وقت کافی ڈسکشن کیا تھا لہذا اب میں زیادہ کہنا نہیں چاہتا مطلب کی حد تک رفر کرونگا۔ ایک سکشن میں یہ پاور دی گئی ہے کہ نٹ انکم (۸) سو روپیہ ہو۔ اوپر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ پانچ آدمی ایسی فیملی ہولڈنگ کو خود کلتیویٹ

کرسکیں۔ اس لئے یہ تھوڑا سا بے معنی ہو جاتا ہے۔ خود کمیشن نے یہ محسوس کیا ہے اس کا کنسپشن یعنی اے فیملی آف پرسنس وہ اس بل سے ان کنسپشنٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نٹ انکم میں ہلو یونٹ یا ورک یونٹ کو پانچ افراد کی فیملی سے متعلق نہیں رکھا گیا۔ کمیشن نے (۸) سو روپیہ کی نٹ انکم کے سلسلہ میں ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی۔ دوسری چیز جسکی طرف میں ہاؤس کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں وہ سب کلاز (۲) ہے۔

“The Government shall determine the extent of land which shall be regarded as a family holding for each class in each class in each kind of soil in all the local areas which may be determined for the State subject to the limits specified below, shall notify in the Jarida the ‘local areas’ and the extents to determine not later than six months from the date on which the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Amendment) Act, 1954, comes into force and shall lay a copy of the Notification before the Legislative Assembly if it is in session, and if it is not in session when it next reassembles.”

اس میں کیا لکھا ہے۔ مختلف گاؤں اور مختلف ایریا کے لئے مختلف ضلعوں میں مختلف قسم کی اراضی کا علیحدہ علیحدہ تعین کیا جائیگا۔ جس وقت یہ چیز پیش کی گئی تھی تو اس وقت ہاؤس میں آئریبل ممبرس آف دی اپوزیشن کی جانب سے اس کے متعلق شبہ ظاہر کیا گیا تھا کہ اگر اس طرح ہم رکھیں تو جس طرح چاہے کمیشن فیملی ہولڈنگ کا ایریا بڑھا سکیگا۔ ہاؤس کی خواہش یہ تھی کہ اس پر لمیٹیشن عائد کیا جائے۔ لیکن اس وقت چیف منسٹر صاحب نے جواب دیا کہ حکومت یا کمیشن لمٹ سے تجاوز نہیں کریگی۔ یہ پرامس تھا۔ یہ کمٹمنٹ تھا۔ اور یہ لمیٹیشن رکھا گیا ہے۔

“Limits:—(1) Wet land—Single Crop each year, all kinds of soils:

- |  |      |         |
|--|------|---------|
| (a) Classification of 8 annas or above | .... | 6 acres |
| (b) All other classes                  | .... | 9 acres |

(2) Dry land:

(a) Black Cotton or laterite soils:

(i) Class I with soil classification

of 8 annas or above .... 24 acres

(ii) All other classes .... 36 acres”



لیکن زیادہ اختلاف وٹ لینڈ میں ہے۔ اس لئے میں اپنی بحث اسی حد تک محدود کرتا ہوں۔ یہاں دفعہ ۴ کے تحت وائولیشن (Violation) ہوا ہے۔ اس ایکٹ کے تحت حکومت پر یہ قید رکھی ہے کہ کسی وٹ لینڈ کی بڑت آٹھ آنے کی ہے تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور اگر اس سے کم ہے تو وہ ایسا بنا سکتے۔ یہ قانون ہمارے اس آنریبل ہاؤس نے بنایا تھا اور جس قانون کو لیجسلیچر نے ایک بار بنایا ہے اسکو اکیڈمیٹو باڈی مولڈ (Mould) نہیں کر سکتی۔ اس کا وائولیشن نہ ہونا چاہئے بلکہ جیسا وہ قانون ہے اسی طرح اس کی پابندی کرتے ہوئے عمل کیا جانا چاہئے۔ چنانچہ کمیشن کے ممبران نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے جو صفحہ ۲ اور ۲۲ پر آنریبل ممبرس ملا ظہ فرما سکتے ہیں۔ میں ان چیزوں میں نہیں جاتا کہ پلو یونٹ ہونا چاہئے یا ورک یونٹ ہونا چاہئے۔ البتہ میری رائے یہ ہے کہ پلاننگ کمیشن نے جو پلو یونٹ اور ورک یونٹ اب رکھے ہیں وہی کامیاب ہونگے اگر ہمیں صحیح معنوں میں لینڈ ریفارم کرنا ہے اور انٹنسیو کلتیویشن کرنا ہے۔ اس پر بحث کرتے ہوئے میں ہاؤس کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ میں صرف ہاؤس کی توجہ اس امر پر مبذول کراؤں گا کہ دفعہ ۴ کے تحت جو اختیارات دئے گئے ہیں ان سے تجاوز کیا گیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کے صفحہ ۲ اور ۲۲ پر یہ کہا ہے کہ

“In view of these facts we would, therefore, be guided more by the condition of the produce than the limits prescribed.....The limits can, we believe, be altered by invoking the proviso to section (4) or if necessary even by an amendment of the Act.”

انہوں نے حکومت کو یہ سبھاؤ دیا ہے کہ یہ لمٹ نکالنا چاہیے یا اس کو عمل میں نہیں لاسکتے تو سکشن ۴ کے تحت جو پراویز ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور امٹڈ منٹ لاسکتے ہیں۔ لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ جب تک ہاؤس اس میں امٹڈ منٹ نہیں کرتا یہ نوٹیفیکیشن بے معنی ہو جاتا ہے۔ غیر قانونی ہو جاتا ہے۔ ڈٹرمنیشن آف فیملی ہولڈنگ (Determination of family holding) کے وقت جو پرائس مارکٹ میں رہیگی اس لحاظ سے ۸۰۰ روپیے رہے اور مزید یہ قید عائد کی گئی ہے کہ کوئی لمٹ ۹ ایکڑ سے نہ بڑھے۔ میں اس پراویز کو بھی ہاؤس کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔

“Provided that the Government may by general or special order direct that the limits of the family holdings specified in this sub-section, shall for any local area be varied if the Government is satisfied that such variation is necessary or expedient for ensuring that the value of produce after deducting fifty per cent. therefrom as cost of cultivation is Rs. 800.”

آپ نے ایک مرتبہ فیملی ہولڈنگ کا تعین کیا۔ اس قانون کے تحت تعین کیا۔ اس کے بعد

حالات بدلے اور پرائس ڈاؤن ہوتی گئیں۔ اس کے بعد حکومت کو یہ احساس ہوا کہ پرائس اتنی نیچے گئی ہیں کہ آٹھ سو روپیہ کی خالص انکم نہیں ہوسکتی اس لئے اس میں تبدیلی کی جانی چاہیے۔ سب سکشن ۲ کی پابندی کے تحت جو ڈکریشن ہوگا اور جو ویاریشنس ہونگے ان سے مطابقت پیدا کرنے کے لئے یہ ایک سیونگ کلاز کے طور پر رکھا گیا ہے۔ لیکن ہاؤس میں ڈسکشن کے جو ٹرنڈس اس ایکٹ پر تھے اور ایکٹ کو بھی پاس ہو کر کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے اوس وقت دونوں بازو سے یہ اصرار کیا گیا تھا کہ کمیشن یا حکومت فیملی ہولڈنگ کو من مانے نہ رکھے بلکہ آنریبل ممبرس کی دی ہوئی رائے پر کافی غور خوض کے بعد فیملی ہولڈنگ کا تعین کرے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ لیجسلیچر اور اکزیکیٹیو میں ہمیشہ جھگڑا ہوا کرتا ہے۔ اکزیکیٹیو ہر وقت زیادہ سے زیادہ پاورس استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے اور لیجسلیچر جو عوام کی رپرینٹیشن ہوتی ہے وہ قانون کے دائرہ عمل میں ورک کرنے کے لئے اکزیکیٹیو کو مجبور کرتی ہے۔ اور ان دونوں کے جھگڑوں کا فیصلہ کورٹ میں ہائیکورٹ یا سپریم کورٹ میں ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک ریزیشن کا کیس ایوان کے ملاحظہ میں لانا چاہتا ہوں۔ قانون میں ہم نے ۶ ایکر رکھا ہے لیکن نظام آباد میں ساڑھے چھ ایکر کا ریزیشن ہوا ہے۔ جب اس نوٹیفیکیشن کے تحت یہ کیس کورٹ میں جائیگا تو یہ رد ہو جائیگا۔ کورٹ اس نوٹیفیکیشن کو قطعاً باقی نہیں رکھیگا۔

دوسری چیز کمیشن نے یہ کنونس کرانے کی کوشش کی ہے کہ لینڈ ریوینیو میں کچھ ڈفکٹس ہیں اور پروڈیوس کی پریس کو اتنا کامپلیکیٹڈ بنایا ہے کہ خود کمیشن کسی ڈفینٹ نتیجہ پر نہیں پہنچ سکا۔ اس لئے انہوں نے آلٹرنیٹیو کے طور پر پرائس کو رکھا ہے۔ لیکن وہ پرائس مشخص کرتے وقت بھی ڈفینٹ نہیں ہے۔ انہوں نے ایک اگزامپل بھی دی ہے۔ انہوں نے ایوریج پرائس کو بیس بنایا ہے۔ انہوں نے جوار چار ایکر میں چار ہلے بتلائی ہے اور اسی طرح دوسرے اجناس بھی بتلائے ہیں۔ گراؤنڈ نٹ اور کائن کے لئے بھی یہ ایوریج پروڈیوس رکھی ہے کہ دو ایکر ہوتو دو ہلے اور تین ایکر ہوتو تین ہلے اور اس کے لحاظ سے ایوریج انکم فی ایکر ۵۰ روپے نکال گئی ہے۔ لیکن جب انہوں نے حدگاؤں اور پاتھری کی زمینات سے متعلق اس اصول کے لاگو کرنے میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے پاتھری رینج ایبلڈ سکس ٹوٹن مانڈ بتلائی ہے۔ اصول تو ایکریج کے لئے ایک ہلہ نکالا ہے تو ظاہر ہے کہ میکزیمم میں فرق آئیگا۔ یہاں اچھی سے اچھی اراضی میں جوار فی ایکر ۶ من ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی اچھی سے اچھی اراضی کا پروڈیوس نکالنے کے لئے انہیں میٹرل نہیں ملا۔ اس لحاظ سے انہوں نے اس کو بھی ادھورا ہی چھوڑا ہے۔

تیسری چیز پرائس کی بابت ہے۔ پرائس دن بدن گھٹتی جارہی ہیں اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ فیملی ہولڈنگ کے تعین کے لئے پرائس (Prices) ایک انسٹیبل الیمینٹ (Unstable element) ہے۔ اس میں

اسٹائیلیٹی کبھی نہیں آئیگی۔ اس لئے قانون بنانے وقت اگر ہمارا مقصد لینڈ ریفارمز کا ہے تو یہ دیکھنا ضروری تھا کہ ایک آدمی دو یا چار پیل رکھ کر کتنی اراضی کاشت کرتا ہے۔ ایک ہیومن پاور کے لئے جہاں تک پاسیبل ہے اتنی اراضی رکھی جاتی۔ چنانچہ پرسنل کلتیویشن کے تحت بھی ہم نے ایک الگ ڈیفینیشن دیا تھا۔ لیکن ان سب چیزوں کو نظر انداز کیا گیا۔ اس سے لینڈ ریفارمز کا مقصد ہی باقی نہیں رہا اور لینڈ لس لوگوں کے لئے کچھ لینڈ نہیں بچ سکی اور جو طریقہ کمیشن نے اختیار کیا ہے وہ غیر قانونی ہونے کے علاوہ ساؤنڈ بیسس پر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اسسمنٹ کے لئے جو رائے ظاہر کی ہے ہم اس سے بالکل متفق نہیں ہیں۔ اسسمنٹ الیمنٹ ہوسکتا تھا لیکن بیس تیس سال میں ایک مرتبہ اسسمنٹ ہوتا ہے اور وہ بھی ایک تعلقہ میں جو اسسمنٹ ہوتا ہے وہ دوسرے تعلقہ میں نہیں ہوتا۔ مال کی نکاسی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو مال حیدرآباد میں بیس میل سے آتا ہے اوس کی قیمت اوس مال سے کم ہوتی ہے جو کہ ۵۰ میل سے آتا ہے۔ اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے جو پرائس اسٹرکچر نکالا ہے اور جو ایوریج ایلنڈ بتلائی ہے اس میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں جو قابل غور ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہی بہت مشکل ہے لیکن اسپرٹ آف دی لا ( Spirit of the Law ) پر نظر رکھنی چاہئے تھی تاکہ لوگوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ اس ایکٹ پر گورنمنٹ نے جو پوائنٹ آف ویو رکھا تھا شروع سے آخر تک وہی پوائنٹ آف ویو ڈامینیشننگ رہا۔ اس لئے آر بیٹریشن وغیرہ کے الزامات سے میں بالکلہ متفق ہوں لیکن انہیں دہرانا نہیں چاہتا۔

دوسرے یہ کہ پیداوار کے تعین میں بھی اختلاف میں نے بتلائے ہیں اور سوائل کے قسم میں بھی اختلافات ہوتے ہیں۔ ایک کھیت سے دوسری کھیت میں زمین مختلف ہوتی ہے لیکن کمیشن نے تعلقہ کو یونٹ بتلایا ہے اور یہ فرض کیا ہے کہ تعلقہ کی پوری زمین اچھی ہے تو اوس سے خراب زمین والوں کو بہت سفر ( Suffer ) ہونا پڑتا ہے۔ یہاں یہ پالیسی ہونا چاہئے تھا کہ کم سے کم لوگوں کا نقصان ہو اور پرت نکال کر اراضی مشخص کی جائے۔ پرسنل کلتیویشن اور روٹیشن آف کراپس سے جتنا فرق پڑتا ہے کمیشن نے اس پر غور کیا ہے لیکن ایک تیز کسان ہو تو اپنے کھیت کو علی الصبح جاتا ہے تاکہ جانور کھیتوں کو نقصان نہ پہنچائیں اور ایک سست کسان ہے تو وہ دیر سے جاتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کھاد نہیں دیتا ہے تو فصل خراب آتی ہے۔ اس لحاظ سے روٹیشن آف کراپس اور پرسنل کلتیویشن میں انیس بیس کا فرق ہو سکتا ہے۔ . . . .

مسٹر چیر من :- آنریبل ممبر کتنا وقت لینگے ؟

شری ادھوراؤ پٹیل :- تھوڑی دیر اس طرح ڈیٹیلز میں جا کر بھی کمیشن کوئی فنڈامینٹل چیز نہیں لا سکا۔ کراپ آلتریشن میں فرق ضرور پڑتا ہے لیکن آئل سیڈس میں اور گراؤنڈ نٹ میں کیا فرق پڑتا ہے اور مختلف چیزوں میں کیا فرق پڑتا ہے اوسکو واضح نہیں کیا گیا۔ اس لحاظ سے کمیشن نے جو بنیادیں لی ہیں اس میں بھی کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ کوئی ڈائریکٹ سپروویژن کرنے والا ہے یا گورنمنٹ سبسائیڈی دیتی ہے یا اسکا

میں پروفیشن (Main profession) (زراعت ہے تو آپ اس کے لئے فارمل حالت میں لے سکتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے روٹیشن آف کرایس میں کچھ زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اگر اس نوٹیفیکیشن کو لیکو کورٹ میں جائیں تو وہ رد ہو جائیگا۔

ایک اور چیز باغات کے تعلق سے ہے جو کنویں سے سینچے جاتے ہیں۔ ہاری طرف بھی پان اور کنڈی کے ملے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ یقین جانتے کہ پانچ ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں کر سکتے اگر اس کے پاس ۱۰ ایکڑ ڈرائی لینڈ ہوتی ہے تو اوسکی طرف کاشتکار کی توجہ نہیں ہوتی۔ بلکہ کنوؤں کے باغات میں اگرچہ خرچہ بھی زیادہ ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ فائدہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن محض اس لئے کہ اخراجات زیادہ ہوتے ہیں کمیشن نے اسکو نظر انداز کیا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔

اور ایک بات مجھے یہ کہنا ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ اتنی طویل لکھی ہے کہ اس میں پورے لینڈ ریفارمس کی ہسٹری آگئی ہے۔ خیر انہیں کاغذ مہیا تھا وہ جتنا چاہے لکھ سکتے تھے۔ سالار جنگ کے زمانہ میں کیا تھا۔ نظام کے زمانہ میں کیا تھا اس کے بعد سنہ ۱۹۵۰ء ایکٹ میں کیا تھا اور پھر ۱۹۵۴ء ایکٹ میں کیا امپروومنٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن میں حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سکشن ۳۸ کے تحت جو پرنسپلز پاور اس قانون کے تحت ملا ہے اور جو چھ لاکھ کی تعداد پروٹیکٹڈ ٹیننٹس کی فیملی ہولڈنگ قائم کرتے وقت بتلائی گئی ہے کیا وہ حاصل ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کے معنی یہ کہ آج جو قانون بنایا گیا ہے وہ محض زمینداروں کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ ایسا قانون ہم بنائے والے ہیں تم اپنی احتیاط کرلو تو یقیناً یہ قانون پیر کی زینت ہو کر رہیگا اور دراصل اس کا مقصد لینڈ ریفارمس نہیں ہے۔

شری داور حسین (نظام آباد) :— مسٹر اسپیکر سر۔ آج جو امر ایوان کے سامنے زیر بحث ہے وہ حکومت کا وہ نوٹیفیکیشن ہے جو ہاؤس کے ٹیبل پر رکھا گیا ہے۔

سری. جی. ڈی. دیشپانڈی:—کيا ऑनरेबल मेंबर लॅंड कमिशन के मेंबर हैं ?

شری عبدالرحمن (ملک پیٹھ) :— پوائنٹ آف آرڈر۔ کیا کمیشن کے ایک ممبر اس رپورٹ پر اپنے خیالات ظاہر کر سکتے ہیں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایوان کو بتلاتا چاہتا ہوں کہ راجیہ سبھا میں ایک سوال آیا تھا اور ڈاکٹر امبیڈکر جو اس کمیشن کے ممبر تھے اس کی رپورٹ پر کہنا چاہتے تھے تو اس وقت وہاں کے ڈپٹی چیرمن جو صدارت کر رہے تھے انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو تقریر کرنے سے منع کیا۔ ابھی کل کی بات ہے۔

شری ادھو راؤ پٹیل :— مسٹر اسپیکر سر۔ یہ کنونشن ڈالنا چاہئے کہ جو سلیکٹ کمیٹی کے ممبرس ہوتے ہیں یا کسی کمییشن کے ممبرس ہوتے ہیں وہ اس کی رپورٹ پر کچھ نہ کہیں۔ ورنہ کمیٹی کا ایک ممبر جو متفق ہے کچھ کہہ سکتا ہے۔

اور جو ڈسٹنٹنگ (Dissenting) ممبر ہے اس کے خلاف کہے تو ہاؤس کی ڈگنی (Dignity) نہیں رہتی ہے۔ چاہے رولس میں گنجائش ہو یا نہ ہو ایسا کنونشن ڈالنا چاہئے۔

شری داور حسین :— میں اسپیکر صاحب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس قسم کنونشن ہمارے پاس پہلے ہی سے موجود ہے اور سلکٹ کمیٹی کے ممبران نے تقریریں کی ہیں مسٹر چیئرمین :— اس قسم کی بحث کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ چیز بالکل علیحدہ ہے۔

شری داور حسین :— اسپیکر سر۔ جو نوٹیفیکیشن آج زیر بحث ہے وہ اس معزز ایوان کے بنائے ہوئے ٹینسی ایکٹ کے دفعہ ۴۴ میں ۲ کے تحت ایوان کے ٹیبل پر رکھا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ جب اس کو ٹیبل پر رکھا گیا ہے تو ایوان میں بحث ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ۲ کے الفاظ یہ ہیں۔

“The Government shall determine the extent of land which shall be regarded as a family holding for each class in each kind of soil in all the local areas which may be determined for the State subject to the limits specified below, shall notify in the Jarida the ‘local areas’ and the extents so determined not later than six months from the date on which the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands (Amendment) Act, 1954 comes into force and shall lay a copy of the Notification before the Legislative Assembly if it is in session, and if it is not in session when it next reassembles.”

میں عرض کرونگا کہ آج ایوان میں جو امر زیر بحث ہے وہ کمیشن کی رپورٹ نہیں ہے بلکہ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے اور نوٹیفیکیشن کا کوئی جزو قانون کے خلاف پڑتا۔ تو آیا اسے آٹرا وائرس قرار دینا ہے یا نہیں۔ . . . . .

(Interruptions)

Mr. Chairman: Order, order.

شری داور حسین :— میں جناب کی رولنگ لینا نہیں چاہتا۔ دراصل اس وقت زیر بحث امر کیا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ نوٹیفیکیشن ہے یا کمیشن کی رپورٹ۔ کمیشن ج مقرر ہوا ہے وہ گورنمنٹ کے ذاتی اختیارات سے مقرر نہیں ہوا بلکہ اس معزز ایوان کے پاس شد قانون کے تحت کمیشن بنا ہے۔ دفعہ ۸۷ (اے) جس کے تحت لینڈ کمیشن بنا ہے وہ میں ایوان کی توجہ میں لاتا ہوں۔

شری عبدالرحمن :— ہم جانتے ہیں۔

شری داور حسین :— جاننے دیجئے۔

Mr. Chairman: Order, order.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—में ऑनरेबल की तबज्जह परेग्राफ अंक की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

“Whereas the Hyderabad Land Commission established under section 87 of the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, 1950 (XXI of 1950) has submitted its recommendations for delimitation of local areas and determination of the extent of the family holdings and the Government accepted the said recommendations.....”

Therefore, this notification is issued.

مسٹر چیرمن :- اس بارے میں رولنگ دی جا چکی ہے کہ رپورٹ پر ڈسکشن ہو سکتا ہے۔

شری داور حسین :- جب معزز اسپیکر نے رولنگ دی ہے تو میں اس کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں لیکن میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں بغیر انٹرپنشن کے بیس منٹ میں کہنے دیا جائے۔ دفعہ ۸۷ (اے) ضمن (۲) کے الفاظ یہ ہیں۔

“Subject to the provisions of this Act and any rules which may be made by the Government in this behalf it shall be the duty of the said Commission to advise the Government in fixing the extent of the basic and family holdings, and the areas to which they apply in matters relating to assumption of management of acquisition of lands by the Government.....”

آج جو رپورٹ ہے وہ اس ایوان کے بنے ہوئے قانون کے تحت عطا کردہ اختیارات کے تحت کمیشن نے پیش کی ہے۔ اس قانون کے تحت جو فیملی ہولڈنگ ہے اس میں کمیشن کو کیا حدود اپنے پیش نظر رکھنا چاہئیں وہ بھی معزز ایوان نے رکھے ہیں۔ اس کو بھی میں ایوان کی توجہ میں لانا چاہتا ہوں۔ دفعہ ۸۷ ضمن (۱) کے الفاظ یہ ہیں۔

“Subject to and in accordance with the provisions of this section, the Government shall determine in the manner prescribed for all or any class of land in any local area or of a family holding which a family of 5 persons including the Agriculturist himself cultivates personally according to local conditions and practice and with such assistance as is customary in Agricultural operations which area, will yield annually a produce the value of which after deducting fifty per cent. therefrom as cost of cultivation, is Rs. 800 according to the price levels prevailing at the time of determination”.

اس معزز ایوان کے بنائے ہوئے قانون میں پلو یونٹ یا ورک یونٹ کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اس میں صاف طور پر یہ صراحت کی گئی ہے کہ پچاس فیصد اخراجات کی منہائی

کے بعد آٹھ سو روپیے کی نٹ انکم یا دوسرے الفاظ میں سولہ سو کی خام پیداوار کی زمین کی فیملی ہولڈنگ قرار دیا جائے۔ لیکن یہ بحث آج اس ایوان میں مختلف طریقوں سے مختلف آنریبل ممبرس نے پیش کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کمیشن نے بہت سی چیزوں کے ساتھ پلو یونٹ اور ورک یونٹ کو بھی ضرور اپنے پیش نظر رکھا لیکن اس کے پیش نظر جو بہت اہم چیز تھی وہ وہی تھی جس کا اختیار اس معزز ایوان نے دیا تھا۔ وہ سولہ سو روپیہ پیداوار کی زمین تھی۔ اس لحاظ سے یہ کہنا کہ پلو یونٹ سے تجاوز کیا گیا ہے یا ورک یونٹ سے تجاوز کیا گیا ہے صحیح نہیں ہے۔

ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہا گیا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ یونانیمس (Unanimous) نہیں ہے۔ صرف ایک ممبر نے اتفاق کیا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ ان اشخاص کے نام جنہوں نے کمیشن کی فائنڈنگس (Findings) پر دستخط کئے ہیں رپورٹ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کمیشن کے آفس میں دستخط کئے ہیں۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—यह आपको कैसे मालूम हुआ कि वहां दरखास्ते आजी हैं ?

شری داور حسین:— میں بھی اس کمیشن کا ایک ممبر تھا۔

*Shri V. D. Deshpande:* The hon. Member speaking as hon. Member of this House and not as a member of the Land Commission.

*Mr. Chairman:* The hon. member cannot disclose all those things.

شری داور حسین:— راجہ رام صاحب نے کمیشن کے ایک ڈسٹنگ ممبر کی حیثیت سے دستخط کیے ہیں لیکن صرف اصولی طور پر وہ ایکٹ سے اختلاف کرتے ہیں کہ فیملی ہولڈنگ پلو یونٹ (Plough unit) ہونا چاہئے یا ورک یونٹ ہونا چاہئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ صرف پلو یونٹ یا ورک یونٹ پر فیملی ہولڈنگ مقرر کرنا کمیشن کو اختیار نہ تھا کیونکہ اس کو اس معزز ایوان نے مسترد کر دیا ہے بلکہ کمیشن کو آٹھ سو روپیہ سالانہ آمدنی ہی دیکھنے کا اختیار تھا۔ چنانچہ راجہ رام صاحب نے اپنے ڈسٹنگ نوٹ میں بھی اس کی صراحت فرمائی ہے۔

اس کے بعد میرے ایک محترم دوست جو کمیشن کے رکن اور اس ایوان کے بھی معزز رکن ہیں اور جن کے ساتھ کلیگ (colleague) کی حیثیت سے کام کرنے کا مجھے اتفاق ہوا انہوں نے کمیشن سے یاہرا کر یہ نتیجہ برآمد کیا کہ کمیشن کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ فیملی ہولڈنگ مقرر کرنا کمیشن کے لئے ہیومنلی امپاسیبل (Humanly impossible) ہے۔ ہیومنلی امپراکٹیکبل (Humanly Impracticable) ہے۔ انہوں نے کمیشن کی رپورٹ کو صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں فرمایا اگر وہ کرتے تو یقیناً ایسے اعتراض نہ فرماتے۔

معزز ایوان اس سے واقف ہے کہ جب کمیشن اون کے مقامات پر پہنچا تو اس نے اس ایوان کے معزز ممبران اور نیز مقامی لوگوں کی خدمات سے استفادہ کیا۔ انہوں نے کسانوں سے استفادہ کیا۔ گرما اور موسم بارش کے زمانے میں جب کہ مقامی عہدہ دار بھی دورہ کرنے سے ہچکچاتے ہیں بلا لحاظ اوقات کمیشن کے ارکان نے دورہ کیا۔ موسم کی خرابیوں کا انہوں نے کوئی احساس نہیں کیا۔ ان پر سن اسٹروک (Sun Stroke) ہوا اس کی انہوں نے پرواہ نہیں کی.....

مسٹر چیر من :- بہتر یہ ہوگا کہ آپ رپورٹ کی تائید میں کچھ کہیں۔

(Laughter)

شری داور حسین :- جو بیانات دورہ کے وقت وہاں کمیشن کے سامنے دیئے گئے اون کے لحاظ سے کمیشن نے سولہ سو روپے خام پیداوار کی زمین کا تعین کیا۔ سارے اسٹیٹمنٹس (Statements) موجود ہیں جنکی بنا پر کمیشن نے نتائج اخذ کئے ہیں۔ اور گورنمنٹ کو اپنے نوٹیفیکیشن کے نتیجہ پر پہنچنے میں جو مدد و معاون ہوئے ہیں اوس کو ملاحظہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی نتیجہ یہاں کے ارکان بھی اخذ کرینگے جو کمیشن نے ارکان نے یا گورنمنٹ نے اخذ کیا ہے۔ کمیشن کا مطمح نظر یہ تھا کہ ملک اور قوم کو فائدہ پہنچے۔ اس موقع پر کمیشن کی پراکٹیکیلیٹی یا امپراکٹیکیلیٹی (Impracticability) سے متعلق کچھ کہنا یا اوس کی رپورٹ کے ان اجزا پر جنہیں امپراکٹیکیلیٹی ظاہر کیا گیا ہے اعتراض کرنا کسی حد تک درست ہو سکتا ہے خود معزز ارکان غور فرما سکتے ہیں۔ میں اس چیز کو معزز ایوان کے احساس فرض پر چھوڑتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اعتراض کے قابل ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ چند چیزوں پر کمیشن نے غور نہ کیا ہو کمیشن نے خود اپنے بیان میں واضح کر دیا ہے کہ اوس کی رائے کن بنیادوں پر ہے اور اوس کے تجاویز کی بیاکنگ (Backing) کیا ہے۔ معزز ارکان کے گھروں پر عین دورہ کمیشن کو گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ اون معزز ارکان کے خیالات سے بھی استفادہ کیا ہے کمیشن کی رپورٹ خود اون کے خیالات کے استفادہ پر مبنی ہے۔ لہذا میں معزز اسپیکر صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ.....

شری. ڈی. ڈی. دیشپانڈے :- آئن ریل ممبر جو تکریر کر رہے ہیں، اوس سے ہمیں کوئی ایترا ج نہی ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کمیشن کے ممبر کو ہئسیت سے تکریر نہیں کر سکتے ہیں۔ انھیں ایک ایم. ایل. اے. کی ہئسیت سے تکریر کرنی چاہیے۔ کمیشن میں جو باتیں ہویں اوسے وہ یہاں پر ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیتنی مالومات ہاؤس کے ممبروں کو ہیں اتنی ہی مالومات انھیں بھی ہیں ایسا مانا جاسیگا۔ کمیشن میں جو باتیں ہویں اوسے وہ ڈیسکلوئر (Disclose) نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ یہاں ایک ممبر کی ہئسیت سے بول رہے ہیں۔

شری داور حسین :- میں عرض کرونگا کہ کمیشن کے کسی عمل سے متعلق احتجاج

کیا جائے اور وہ ارکان یہاں موجود ہوں تو.....

مسٹر چیر من :- کمیشن کے طریقہ کار یا انریبل ممبرس کے بارے میں ریمارک



شری داور حسین :- چونکہ اعتراض کیا گیا تھا اس لئے . . . . .

شری پنڈم واسدیو (گجویل) :- اعتراض کا سب کو حق رہتا ہے۔

شری داور حسین :- ایک اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ ریونیویس (Revenue basis) پر مبنی کی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا گیا ہے ریونیویس کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوس اعتراض کے وقت کمیشن نے جو راستہ اختیار کیا تھا اوسکو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ایلڈ (Yield) ریونیو اور کلاسیفیکیشن آف سوائل کو ہم نے ریونیویس کے ایک جزوی حیثیت سے رپورٹ میں ملحوظ رکھا ہے۔ جس حد تک ریونیویس سے ہم استفادہ کر سکتے تھے ہم نے استفادہ کیا ہے یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بالکل مالگزار کے عنصر کو نظر انداز کر دیا گیا ہے یا کلیتہ مالگزاری کی بناء پر رپورٹ مرتب کی ہے۔

شری. سکماजी घोंडीबा पाटील (आष्टी) :- मौजूदा रुकन एक जिम्मेदार रुकून हैं और अन्हें जिसके बारे में काफी जानकारी भी है। सब लोगों के भाषण होने के बाद अगर वे अपनी तकरीर करें तो मुनासिब होगा ऐसा मेरा ख्याल है।

شری داور حسین :- اس کے بعد کمیشن کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ لوکل ایریا کس طرح بنانا چاہئے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک اڈوائزری باڈی ہے۔ کمیشن کے سامنے ایسے تجاویز آئے کہ دو آنے۔ چار آنے۔ آٹھ آنے کلاسیفیکیشن کی زمین کے لئے بھی الگ الگ فیملی ہولڈنگ بنائے جائیں ایسے تجاویز بھی آئیں گے کہ مرھٹواڑی کے لئے الگ۔ تلوگانے کے لئے الگ اور کرنائک کے لئے الگ لوکل ایریا بنائے جاسکیں۔ ان حالات کے تحت کمیشن نے جو مناسب سمجھا اوسکو گورنمنٹ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب نتائج کا اخذ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اون بنیادوں پر گورنمنٹ نے جو نتائج اخذ کئے وہ خلاف قانون نہیں ہیں۔ بعض اراکین نے یہ اعتراض کیا کہ کمیشن نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے۔ جس مقام پر کمیشن نے یہ محسوس کیا کہ سولہ سو کی پیداوار کے لئے کس قدر زمین ضروری ہے تو صاف طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا کمیشن نے بہت سی جگہ یہ محسوس کیا کہ لمٹ (Limit) کے اندر پیداوار اتنی برآمد نہیں ہوگی مثلاً تری کے چھ ایکڑ میں سولہ سو کی پیداوار بہت سی جگہ برآمد نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ آٹھ آنے سے کم کلاسیفیکیشن کے لئے ۹ ایکڑ کا رقبہ معین کیا گیا لیکن بطور واقعہ تری میں آٹھ سے کم کلاسیفیکیشن نہیں ہوتا یہ تمام چیزیں معزز گورنمنٹ کے پاس ہم نے پیش کر دی ہیں۔ اور یہ بھی بتادیا کہ کس قدر رقبہ سے البتہ سولہ سو کی پیداوار برآمد ہو سکتی ہے۔ یہ رقبہ آیا قانون کے حدود متجاوز کر کے مقرر کیا جاسکتا ہے یا خاص اختیارات کو استعمال کر کے حد بندی کیجا سکتی ہے۔ اس پر غور کرنا حکومت کا کام تھا میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں اور خود اس معزز ایوان نے (For all Classes of land) کے الفاظ میں فیملی ہولڈنگ مقرر کرنا جو اختیار دیا ہے اوس کے مد نظر گورنمنٹ کو اختیار ہے کہ جملہ کلاس کی اراضی کے لئے ایک فیملی ہولڈنگ مقرر کرے جو کسی طرح خلاف قانون

ایک اور چیز اراضیات زیر باؤلی کو خشکی میں شامل کرنے سے متعلق معزز ارکان نے فرمایا۔ اس کے متعلق مختلف بحثیں ہوئیں۔ بعض ارکان یہ قرار دیتے ہیں کہ تلنگانے کے رقبہ کو خشکی نہیں قرار دینا چاہئے۔ بعض مرھٹواؤں کے رقبہ کے متعلق کہتے ہیں کہ خشکی میں شامل کرنا چاہئے۔ زیر باؤلی کاشتکاری میں کاشتکار اپنی محنت سے اراضی سینچتا ہے۔ زیر باؤلی کے رقبہ کو مستقل طور پر معین کرنا مشکل ہے کیونکہ ایک سال وہ مشرق میں کاشت کرتا ہے تو دوسرے سال مغرب میں۔ کبھی کسی رقبے میں کاشت کرتا ہے تو کبھی کسی رقبے میں۔ پھر یہ بھی کوئی قانونی پابندی نہیں ہے کہ جو رقبہ زیر باؤلی کاشت ہوتا ہے وہ مستقل زیر باؤلی ہی کاشت ہوتا رہے جبکہ غیر معمولی مصارف اس کاشت پر کرنے پڑتے ہیں۔ ان تمام امور پر غور کرنے کے بعد اس کو خشکی کے تحت قرار دیا گیا ہے جو درست ہے نظام آباد کے نیشکر کے رقبہ میں سولہ سو روپیہ کی پیداوار ایک ایکڑ کے رقبہ میں ہوسکتی ہے۔ معزز ارکان کو بتانا چاہتا ہوں وہاں جو اعداد جمع کئے گئے تھے اُن سے پتہ چلتا ہے کہ مستقل نیشکر کی جو کاشت کرتے ہیں وہ صرف وہاں کے بڑے فارمس کرتے ہیں۔ بیشتر چھوٹے کاشتکاروں کا حصہ وہاں بھی دھان کی کاشت ہی کرتا ہے علاوہ ازیں دو سال میں نیشکر کی فصل تیار ہوتی ہے اسکے بعد وہاں سے روٹیشن کیا جاتا ہے اور چوتھے سال پڑاؤ چھوڑا جاتا ہے تاکہ زمین کو آرام ملے۔ اس لحاظ سے جو رقبہ معین کیا گیا ہے وہ صحیح ہے۔ ان تمام حالات کے لحاظ سے معزز ایوان سے عرض کروں گا کہ کمیشن نے کسی جگہ اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کی ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اُس نے اپنے فرائض سے کوتاہی کی ہے تو سنسیور (censure) کریں کھلے دل سے اعتراض کریں اور اس پر ملامت کریں۔ لیکن جس حد تک انہوں نے مفید کام کیا ہے وہ اسی ایوان کے ایک تعمیل کنندہ کی حیثیت سے کام کیا ہے محض اعتراض کی بجائے کنسٹرکٹیو (constructive) تنقید ہو تو ہمت افزائی کے قابل ہوتی ہے۔ ہمیں حالات پر غور کر کے تنقید کرنی چاہئے۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

श्री. गोविन्दराव नरसिंगराव मोरे (कंधार-आम) :—जिस रिपोर्ट पर जो डिस्कशन हो रहा है, उसमें बहुत से अजरात अठाये गये और वह बड़ी हद तक सही हैं। हमने दफा ४ के तहत फैमिली होल्डिंग ( Family Holding ) का तायुन करने की गरज से लैंड कमीशन जिस-लिये मुकर्रर किया था कि हम कुछ सही नतीजें पर पहुंचेंगे। लेकिन रिपोर्ट के पढ़ने से जैसा कि बहुत से मेंबरों ने कहा कि पहाड खोद कर चूहा निकाला गया है लेकिन मैं तो कहूंगा कि यह हमारे अग्रीकल्चरल अकॉनामी के गोदामोंमें अक घूस छोड दी गयी है। किसान के अर्थ शास्त्र के गोदाम को बड़ी बड़ी मेंगे गिरा देगी। जिस वक्त कमीशन के मेंबरों का तकईर हो गया हम समझते थे कि यह ज्यादा फायदेमंद काम नहीं होगा। तेलंगाने की हद तक अच्छे माहरीन वहां थे, जिसलिये वहां अच्छी फैमिली होल्डिंग हो सकी, लेकिन मराठवाडे का रिप्रेजेंटेशन ( Representation ) सही तरीके से न होने की वजह से मराठवाडा और करनाटक में जिसका बुरा असर पड़नेवाला है। वहां की फैमिली होल्डिंग अच्छी से अच्छी जमीन के लिये २१ अकड है।

श्री. गोविंदराव नरसिंगराव मोरे:—हां, ज्यादा होना चाहिये। यह काश्तकारों के कानून जो सिर्फ किताबी दुनिया में काश्तकारी असूल पढ कर राय कायम करते हैं, उनके लिहाज से ठीक हो गया है, लेकिन २५ अेकड के काश्तकार को अगर आप पूछें कि चार या पांच आदमियोंकी फैमिली के लिये क्या यह होल्डिंग काफी हो गयी है, तो वह क्या कहेगा? आप कहेंगे कि फैमिली होल्डिंग कम होने से ज्यादा से ज्यादा जमीन तकसीम हो जायेगी तो फायदा होगा, ऐसा नहीं है। जो भीमानदारी से काश्त करना चाहता है, वह बहुत छोटी फैमिली होल्डिंग से जरूरी आमदनी पैदा नहीं कर सकता। मैं मानता हूं कि फैमिली होल्डिंग जितना कम करेंगे उसके मुताबिक लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन (Distribution) होगा, लेकिन इस वक्त के हालात से फैमिली होल्डिंग मुकर्रर करें तो वह ऐसा होना चाहिये कि जिससे काश्तकार अपनी जिंदगी बाजिज्जत बसर कर सके। अेकबात इसमें कही गयी है कि कमीशनने इससे बचनेके लिये समझिये या और किसी वजह से हो, दस साल का रेनफॉल (Rainfall) बताया गया है। सफे ४६ पर परभणी, नांदेड, करीमनगर और मेदक अनिको देखें तो उनका रेन फॉल ३० या ३२ इंचेस बताया गया है। इस तरह से नांदेड के बारे में कहा गया है और इस पर से वहां की यील्ड (Yield) का तायून किया गया है। हर यील्ड ५५ रुपये बताया गया है। अगर यह हो तो आज के हालात में कम से कम फैमिली होल्डिंग २८ अेकड से भी ज्यादा होना चाहिये। बाज जगह २१ और बाज जगह ३६ अेकड भी रखा गया है। अधर तेलंगाने में आठ आने के नीचे की जमीन का खयाल रखा गया है, लेकिन मराठवाडे और कर्नाटक में आठ आने की जमीन ही नहीं है, ऐसा कह कर टाल दिया गया है। इससे हमारे काश्तकारों को बहुत नुकसान हुआ है। इसलिये इस फैमिली होल्डिंग पर नजरसानी करनी चाहिये। अगर मेंबर माधवराव कमिटी की नोटीस देखते तो अितने बयानात भी लेने की जरूरत नहीं थी। काफी बयानात और स्टेटमेंटस कमिटी ने लिये, रेकार्ड देखे गये। जंग के जमाने में तो प्राजिसेस बढी हुयी थीं। उस वक्त के पैदावार के आंकडे लिये जाते तो उनको मालूम हो सकता था कि कितने फैमिली होल्डिंग रखने की जरूरत है। रेवीन्यू डिपार्टमेंट के कागजात को देखकर ही आखिर इस नतीजे पर पहुंचनेवाले थे तो इस तरह की बदतरीन फैमिली होल्डिंग मराठवाडे और कर्नाटक के लिये नजर नहीं आती। अेक आनरेबल मेंबर ने कहा कि अगर आप फैमिली होल्डिंग बढायेंगे तो काश्तकार का फायदा नहीं होगा, उसमें उसकी गुजर बसर नहीं होगी। मुन्होंने अपना खर्च बताया। बावजूद इसके कि फैमिली होल्डिंग छोटा करने से बडे जमीनदार खतम हो जायेंगे ऐसा वे समझते हैं। आपका कानून आने के पहिले ही मुन्होंने अपनी जमीनात का बंटवारा कर लिया है। इसलिये मैं कहता हूं कि यह अेक फैमिली होल्डिंग का भूत हमारी अेग्रेरियन अेकॉनामी में छोडा गया है। इसलिये ड्राय लैंड के लिये नजरसानी होनी चाहिये। वह न की जायेगी तो काश्तकारों को नुकसान होगा। फैमिली होल्डिंग छोटा होने से जमीन की तकसीम करनी पडेगी ऐसा आपका कहना है, लेकिन आप नहीं जानते कि ढाजी अी अेकड के लिये पांच पांच कत्तल मराठवाडे में हुये हैं। आप कहते हैं कि इससे रेव्होल्यूशन (Revolution) होगा लेकिन मैं समझता हूं कि यह अेंटीरेव्हल्यूशन (Anti-revolution) हो जायेगा। नांदेड जिले में बाज जगे तीस अेकड फैमिली होल्डिंग बनाया गया है। कंधार को तो दो हिस्सों में तकसीम किया जाना चाहिये था, इसकी वजह यह बतायी गयी है कि ऐसा नहीं करते तो गिरदावर सर्कल को तोडना पडता और उससे बहुत मुश्किल हो जायेगी।

मैं अर्ज करूंगा कि जो फॅमिली होल्डिंग कायम की गयी है उस पर फिर से नजरसानी होनी चाहिये अगर काश्तकार अके या दो अकेड में भी जिज्जत के साथ अपनी जिन्दगी बसर कर सकता है तो मुसीको आप फॅमिली होल्डिंग करार दें। नहीं तो अितनी जमीन को फॅमिली होल्डिंग करार दिया जाना चाहिये जिससे वह अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बसर कर सकेगा। अितना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री. खन्नाजी घोंडीबा पाटील :—अध्यक्ष महोदय, जिस लैंड कमिशन की रिपोर्ट पर अधर और अधर से जो बहुत हुजी, उसको सुनने के बाद मुझे भी अच्छा हुजी कि मैं भी जिस पर कुछ कहूं। वक्त का तकाजा और मौजूदा हालात को देखा जाय तो जिस रिपोर्ट से बहुत ज्यादा नुकसान होने-वाला है, ऐसा कहने के लिये मैं तैयार नहीं हूं। जिस वक्त मौजूदा हालात में मेहनत कर रहे थे उस रिपोर्ट की ताजीद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। रिपोर्ट में कानून के अल्फाज का पालन करते थे जो सोलह सौ रुपये फॅमिली होल्डिंग के लिये तय किये थे, उसमें आधा हिस्सा खर्च का निकाल दिया जाय तो आठ सौ रुपये बच जाते हैं। मैं मराठवाड़े की इतना कहता हूं कि वहां के मजदूर को कम से कम १२ आने से अके रुपये तक रोजी मिलती है। अगर मजदूरों के पांच लोगों की अके फॅमिली काम करे तो साल भर में करीब १६०० रुपये होते और काश्तकार के पांच आदमियों की अके फॅमिली अगर अके फॅमिली होल्डिंग की जमीन में मेहनत करे तो जो कमाती है वह भी १६ सौ रुपये होते हैं। यहां पांच आदमियों को आठ सौ रुपये बचते हैं तो जो खेत में मजदूरी करता है उससे भी यह कम हो गया है, यानी आज के काश्तकारों की हालत उस कानून के तहत मजदूरों से भी बदतर हो गयी है। यानी मजदूर और काश्तकार अके ही किसम में हो गये हैं। देहातों में अस्सी परसेंट जो गरीब लोग-संख्या है, वह तो मसावी दर्जे पर आ गयी है। उस कानून के तहत हम कह सकते हैं कि अपोजीशन का मसला और हमारा मसला अस्सी परसेंट पाप्यूलेशन तक तय हो गया है। अब रहा बीस परसेंट पाप्यूलेशन का सवाल। जिस रिपोर्ट पर लैंड रिफार्म्स पर जो अंतराजात किये जा रहे हैं वे सही नहीं हैं। अधर और अधर वास्तव में जो खटकता है वह अिन बीस परसेंट लोगों के बारे में खटकता है, और वे लोग सरमायेदार हैं। तब साथ उसमें वकील, डाक्टर, कारखानेदार यानी कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने वाले। सच पूछा जाय तो जिस सीलिंग के बारे में हाथुस में कोजी अंतराज नहीं है। जो कुछ अंतराज वह अिन बचे हुअे बीस परसेंट लोगों के बारे में है, और गवर्नमेंट के लिये जो काम बाकी रहा वह अितना ही है कि अिन लोगों के लिये सीलिंग लागाना चाहिये। अब साठे चार फॅमिली होल्डिंग खने से यह मसला तय होने वाला है या नहीं यह सवाल रह जाता है। देहात में जाकर लोगों से उसके बारे में पूछेंगे तो उनकी राय मालूम होगी। लैंड कमिशन के मेबर और हम लोग अकेसा हैं। कानून को बरकरार रखते हुअे जितना कुछ हो सकता है, लैंड कमिशन ने किया है और जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, उसके अलावा और जिससे बेहतर तरीके की रिपोर्ट हम या आप नहीं बना सकते हैं। अपोजीशन के पूरे के पूरे मेबर भी कमिशन में रखे जायें तो वे जिससे बेहतर रिपोर्ट ही बना सकते। आज काश्तकार के दिल में अगर कोजी बात खटकती हो तो वह यह नहीं है कि से ज्यादा जमीन दी जाय या कम लेकिन वह यह है कि जो जमीन हो वह बागायती जमीन हो। बेदाक ही हो लेकिन जिज्जत कमानेवाला हो। वह चाहता है कि जमीन कम मिले लेकिन वह बागायती

जमीन मिले। जिसलिये अपोजीशन को और हमको मिल कर यह तय करना चाहिये कि बागायती जमीन किस तरह से काश्तकार को मिल सकेगी। सौ अकड़ खुस्की जमीन रहे तो उससे कोजी फायदा नहीं होता। अकड़ दफा हमारे जिलाके में अकाल पडा तो पानी न होने की वजह से सब लोग दूसरी जगह चले गये। वहां उनको पानी मिल सकता था। हमारे घर के कुछ लोग वहीं रहे क्योंकि उनकी बावली में थोडा बहुत पानी मिल जाता था। बाद में रेवीन्यू वसूल करने के लिये अधिकारी आये। उन्होंने देखा कि लोग वहां नहीं है, तो उन्होंने जो लोग वहां हाजिर थे, उन्हें से सारा रेवीन्यू वसूल किया। मेरे घर के लोगों ने गवर्नमेंट की मालगुजारी दे दी। बाद में वे कलेक्टर के पास गये। उनको बताया कि यह कहां का ज़िन्साफ है कि सारी वसूली हम से की गयी? तो कलेक्टर ने कहा तुमने मालगुजारी दी जिसलिये पूरे गांव का पट्टा तुम्हारे नाम पर हो जायेगा। जिस तरह के उस वक्त अधिकारी थे, गवर्नमेंट थी और ज़िन्साफ था। जिस तरह से देखें तो हमें जिस रिपोर्ट को बुरा नहीं समझना चाहिये। सौ अकड़ रखनेवाले लोगों के पेट का मसला जिससे हल होता तो अकाल पडने पर वह दूसरे गांव में नहीं चले जाते। मेरा कहना है कि आपको अंतराज करना है तो वह बागायती जमीन के बारे में कर सकते हैं। मराठवाड़े की जमीन नापीक है वह कम की जाय या ज्यादा की जाय, उससे कोजी फर्क होनेवाला नहीं। मान लीजिये हमारे मुल्क में साठे तीन करोड़ अकड़ जमीन है और आबादी पावने दो करोड़ है। जिस आबादी में से २० परसेंट लोगों को निकाल दिया जाय और बाकी लोगों में जमीन तकसीम कर दी जाय तो हर अकड़ मनुष्य के लिये अकड़ या सच्चा अकड़ जमीन मिलेगी। जिस दृष्टि से हर अकड़ फॅमिली के लिये पांच अकड़ बागायती जमीन रहना जरूरी है। पेट भरने का मसला तभी हल होगा जब बागायती जमीन ज्यादा होगी।

अब बावलियों की जमीन को बागायती जमीन करार देने का सवाल हमारे सामने भुठाय गया है। मैं जानता हूं कि गरीबों से हमदर्दी रखनेवाले सभी मॅबर जिस हाउस में हैं, लेकिन हमारे जिलाकों में बावलियां खोदी गयीं, लेकिन बारिश न होने की वजह से पानी का लेवल नीचे गया। ऐसी हालत में कैसे कहा जा सकता है कि बावलियों की जमीन को बागायती जमीन करार दिया जाना चाहिये? बागायती जमीन उसको कह सकते हैं कि काश्तकारने भोट पकड़ने पर उसको पानी मिल सके। लेकिन जिस तरह की बावलियों के नीचे आनेवाली जमीनात को बागायती जमीन करार दिया जाय तो गरीबों का बहुत नुकसान होगा। गवर्नमेंट अपनी पूरी ताकत तालाब बनाने के लिये खर्च करेगी और अिन बीस परसेंट लोगों पर सीलिंग कायम करेगी तब यह मसला हल हो सकता है। और तब हम आपके अंतराजात को मानने के लिये तैयार हो सकते हैं।

यह भी अंतराज किया गया है कि फॅमिली होल्डिंग रेवीन्यू बेसिस पर होना चाहिये, लेकिन आप नहीं जानते कि अकड़ जमाने में यह रेवीन्यू किस तरह से फिक्स किया गया था। पैमायेस पाटियां जिस गांव में आती थीं उस गांव के लोग चंदा जमा करके उनको हजार दो हजार रुपये दे देते तो उनके गांव का रेवीन्यू कम हो जाता था। पच्चीस साल तक मुसलसिल में देहातों की सेवा करता रहा हूं, जिसलिये ये चीजें मुझे मालूम हैं। जिस तरह से जो रेवीन्यू तय किया गया है उसको बेसिस समझ कर अगर हम फॅमिली होल्डिंग तय करें तो कितना अन्याय हो सकता है किसका

अंदाजा किया जा सकता है। उसमें जो गुंजायिश उस वक्त बतलाया गया है कि जो गांव रास्ते-पर होंगे, मार्केट प्लेस के नजदीक होंगे उनका रेवीन्यू ज्यादा होगा लेकिन जो रास्तों से दूर होंगे या पहाड़ों के अंदर होंगे तो उनका रेवीन्यू कम होगा। रेवीन्यू एक जमाने में किस तरह से तय किया गया है वह मैंने तबलाया और उस दृष्टि से रेवीन्यू बेसिस पर फॉमिली होल्डिंग रखना बिल्कुल गलत है। उससे यह मसला हल होने वाला नहीं है।

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

यह भी एक अंतराज किया गया कि चराबी के लिये जमीन क्यों छोड़ते हैं ? अगर आप खुद काश्तकार होते तो आपको मालूम होता की चराबी के लिये जमीन छोड़ने की क्या जरूरत है ? जिसके पास चार पांच बैल जोड़ी है और उसके जरिये वह अपनी काश्त करता है तो वह अपने बैलों को क्या खिलायेगा। जिस लिये चराबी के लिये जमीन छोड़ना बहुत जरूरी है ऐसा मेरा ब्याल है। साढेचार फॉमिली होल्डिंग की जमीन पर्सनल कल्टिवेशन के लिये छोड़ी गयी है, तो अनिसे हो सकता है कि काश्तकार और मजदूर एक जगह आ सकते हैं। पहले जो काश्त कार थे वे आज उनकी जमीन जाने के कारण मजदूर होगये हैं। जिस लिये हद लगायी गयी है कि साढेचार गुना फॉमिली होल्डिंग से ज्यादा जमीन कोबी नहीं रख सकता है। रेवीन्यू की आम-दनी बढाने की जिम्मेदारी भी सरकार पर रहती है। रेवीन्यू अदा करने की जिम्मेदारी काश्तकार पर होती है। मालिक जो होता है उसे रेवीन्यू अदा करना पडता है। जिस लिये मालिक और मजदूर अलग हो सकते हैं। रेवीन्यू अदा करने की जिम्मेदारी मालिक पर होनी चाहिये। जिस लिये आनेवारी बेसिस करने की गुंजायिश नहीं है। वक्त काफी हो रहा है और अब मैं जल्द ही अपनी तकरीर खतम करता हूं।

हमारे पास ज्यादा जमीन तालाब के नीचे लाने की जरूरत है। मराठवाडे में तालाबों के नीचे बहुत कम जमीन है। मराठवाडे के जमीन के बारे में अब मैं कुछ कहना चाहता हूं लेकिन अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगा।

The Bell was rung

यह कहा गया कि यह जो रिपोर्ट पेश की गयी उससे हमें जिनसाफ नहीं मिलनेवाला है, लेकिन यह मानना गलत है। आज कांग्रेस की पाप्पुलर गव्हर्नमेंट है और अन्होंने यह रिपोर्ट आपके समाने रखी है तो जिनसाफ जरूर मिलेगा, जिसमें मुझे कोबी शक नहीं है। लंड कमिशन के बारे में जो बहुत से अंतराजात अुठाये गये वह ठीक नहीं हैं। बोल्ने के लिये तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उसमें उदाकत नहीं है। जमीन डिस्ट्रिब्यूशन के लिये मिले, जिस लिये सिर्लिंग जल्द से जल्द लागाने की जरूरत है, ताकि हमें जल्द से जल्द ज्यादा जमीन मिल सकें। जितना कहते हुये मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

ಶ್ರೀ ಎಲ್. ಕೆ. ಸರಾಫ್ (ರಾಯಚೂರು.) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾಶಯರೇ,

ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅರಿಯದ ಹಲವು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪಯೋಗವಾದರೂ ಆಗಲೆಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವೆನು.

ಈ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿಗೆ ಆಭಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟು, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ಭಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪದೆ ಹೊಳೆಯದಿರದು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಈ ಕಮೀಷನ್ ಇವುಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ತರಹದ Understanding ಗೆ ಬಂದಿದ್ದುವೇನೇ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಾಗ್ಗೆ ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಏನಿದ್ದುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಸದಸ್ಯರ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಿವೆ ಎನ್ನು ಬಹುದು. Preconceived notions have played a part in coming to the conclusions that the Commission has come to" ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದೇನೆಂದರೆ "Family Holding" ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿ : ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರು ಯಾವ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಒಂದೆರಡು ಏನೋ ಬಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಎತ್ತುಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲದು, ಒಂದು ಜೋಡು ಎತ್ತು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ಅದು ನಿರ್ದೋಷಿಯಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡು ಎತ್ತನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ, ಸರಾಸರಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ಬಾಬಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

"The Land Commission seems not to have taken into account at any rate one factor, that is the amount that would have to be invested upon the cattle in carrying on Agricultural operations".

ಈ ಮಾತು ಏಕೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಂದರೆ, ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಈ ವಿಷಯವೇ ಅಲ್ಲದೆ Insurance, ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರುವುದು ಒಂದು ಸೋಪಗದ ಸಂಗತಿ. ವಿಶೇಷ ಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವಾಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನ ಸದಸ್ಯರು ತಮಗೆ ಈ ಕಾನೂನಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅವರು ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಿಪೋರ್ಟು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ತಡ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ತರದ ಕಾನೂನಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲೇ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕಲಮಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ನೋಡಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟೇ ಯಾವ ಕಾನೂನಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮನ್ನು ಕಾನೂನು ಮಸೂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಾಗ್ಗೆ ಸರಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿಯೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.

“Section 4 of the Act was placed before the House as a clause of the Bill by the Government itself, but the Government seems to have even then had no confidence in its own recommendations to the House in the form of this Clause.”

ಅದಕ್ಕೇನೇ ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯಾದ ಕೂಡಲೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ತರದ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ನಿರ್ಣಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಾದರೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ಎಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿವರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನಗೂ ಮುಂಚೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸದಸ್ಯರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರು ಹೇಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಹಿಡುವಳಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಚ್ಚುಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವರದಿಯ ೨೪ನೆಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ೬೦ನೆಯ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸರಾಸರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:—

“Simplicity of formulas can be achieved by broad averages and by providig enough latitude for variations.”



ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ:

“As an illustration we may examine how latitude allowed would actually work upon both the landlords and tenants. If a Family holding calculated at 24 acres for a local area is for averages fixed at 30 acres the increase would operate as follows:”

ಹೀಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮಾಲಿಕರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯಾಂಶಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ೨೬ ಎಕರೆ ಯಿಂದ ೩೦ ಎಕರೆಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಕ್ಕುವುದೋ ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ರಕ್ಷಿತಕುಳಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಒಡೆಯನಿಗೆ ಆರು ಎಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಫಲವಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯ ೧೨ನೆಯ ಪುಟ, ಪ್ಯಾರಾ ೩೦ ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ:

“It would be worthwhile to see how and how far the Hyderabad Tenancy and Agricultural Lands Act, as amended by the Amendment Act, of 1954, provides for fulfilling some of the main objectives of the Land Reform policies in the country. These objectives are:

- (i) Augmentation of Agricultural production by a better system of land management;
- (ii) Reduction of inequalities, inopportunities and income; and
- (iii) Provision of security for tenants including opportunities for them to become owners of the land they cultivate”.

ಈ ಮೂರು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾಯಿದೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಗಳೆಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳ ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಫಲವಾಗಿವೆ, ಅಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು (Chapter) ಸೇರಿಸಿದ್ದರೆ ಅದರ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ವರದಿಯೇನೂ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರಂತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿತಕುಳಗಳಿಗೆ “Security of Tenants” “Reduction of inequalities in opportunities and income” ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎದೆತಟ್ಟಿಹೇಳುವರೇ? ನಾನೇನೋ ನಂಬಲಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ: ಅದರಿಂದ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾದ ವರದಿಯಾಗುವುದೆ ಹೊರತು ರಕ್ಷಿತಕುಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ವರದಿಯಾಗಲಾರದು. ಯಾವ

ಭೂಸುಧಾರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತರಲಾಗಿತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಮೀಷನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು (Irrational) ಎಷ್ಟು ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೆ ಇಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಎರಿಭೂಮಿ ಎಂದರೆ, (Black Cotton Soil) ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಕಮೀಷನ್ನು ಎರಿಭೂಮಿ ಸರ್ಭಣಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜಿನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷಗುಣಗಳುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇನೆಯ ಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ :

“Deficit rainfall is a great handicap for Raichur District. Otherwise Sindanoor and Manvi might have ranked among the riches in the State”.

ಆದರೆ ಇದೇ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುಟುಂಬಹಿಡುವಳಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವಾಗ ಈ ಮಾತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ನಿನವರಿಗೆ ನೆನಪಿರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ೩೦ ಎಕರೆಯನ್ನೇನೋ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅವರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಲಮಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಪ್ಪು ಅಳತೆಯ ಕೋಲನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾದ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಫಿರ್ಕಾಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಎರ್ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದೂಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. (Simplicity) ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ ! ಇನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಕಡೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ೩೦ ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ರಾಯಚೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಎರಿಭೂಮಿಸಿ ಗುತ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಸಾರೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ತರದ ಉಸುಲು ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಗಳೂ ಎಂಟು.

“Not even a blade of grass in eastern parts of Raichur.

ಆದರೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ೩೦ ಎಕರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

“One of the richest black-cotton soils has been clubbed with the worst variety of chalka lands where not even a blade of grass grows.”

ಇದು Rational ಆಗಿದೆಯೇ? ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ನ್ಯಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಎರಡೂ ಸಮನಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು (argument) ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಮೀಷನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಚಾರಮಾಡಬೇಕು,

ಇಂತಹ ಅಸಮಂಜಸ ವರದಿಯನ್ನು ಇಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರವೂ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಅವಸರದಿಂದ (Hastily) ಉಪಯೋಗಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಮಾಲಿಕರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಿತ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ರಕ್ಷಿತ ಕುಳಕ್ಕಂತೂ ಸಹಾಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೇನೂ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗೆ ತರುವ ಒಂದು ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದೆಯೆಂದು ಯಾರೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

### Half-an-hour Debate.

(ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಯಶ್. ನರಸಿಂಹರಾವು (ಎಲ್ಲರೂ—ಜನರೊಡನೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷಮಹಾಕಯಾ,

مسٹر ڈپٹی اسپیکر:— آپ ہندی میں فرمائیں تو زیادہ اچھا ہوگا اور منسٹر صاحب کو جواب دینے میں آسانی ہوگی۔

شری کے - ایل - نورسما راؤ:— اسپیکر سر - تعلقہ یلندو کے موضع گادے پاڑو میں پولیس امین مادھو راؤ کے جو مسلسل مظالم جاری ہیں اس سلسلے میں میں نے اسمبلی میں کئی سوالات پیش کئے ہیں - وہاں کے اصلی واقعات کو جاننے کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ اصلی واقعات کیا تھے - یہاں جوابات غلط طور پر دیئے جاتے ہیں - وہاں کے عہدیداروں کی رپورٹ کی بنا پر کہہ دیا جاتا ہے - موضع کوئلہ گورہ گاندھی نگر میں وہاں کے زمیندار جناریڈی جگناتھ ریڈی کی وہاں ذاتی زراعت بالکل نہیں ہے - وہ پوری کی پوری اراضی رعایا کے قبضہ میں ہے - یہ حیثیت ٹیننٹ وہ کاشت کر رہے ہیں - گذشتہ تین سال سے ان اراضیات سے ان لوگوں کو ییدخل کرنے کی کوشش کی جارہی ہے - لیکن وہاں اس حلقہ کے سب انسپکٹر مادھو راؤ اور تحصیلدار لنکا وشوانادھم کے آنے کے بعد ( جو وہاں کے زمینداروں سے مل گئے ہیں اور پیوٹ بھی ہیں - خیر میں اون کے ذاتیات پر حملہ کرنا نہیں چاہتا ) وہاں کے حالات خراب ہو گئے وہ ٹیننٹس کو ییدخل کرنے میں زمینداروں کی مدد کر رہے ہیں - اونکے مشورہ پر زمیندار محبوب آباد سے غنڈوں کو لاتے ہیں اور کسانوں پر حملہ کیا جاتا ہے - کسانوں کی طرف سے رپرزنٹیشن ( Representation ) کرنے پر بھی کوئی توجہ نہیں کی جاتی ہے - وہاں افضل بی نامی ایک عورت پر ریپ ( Rape ) کرنے کی اون غنڈوں نے کوشش کی - اس کی پاداش میں اون غنڈوں پر مقدمات چلانے کی بجائے سب انسپکٹر نے مظلوم عورتوں اور انکے مردوں کو گرفتار کر کے اون پر جھوٹے مقدمات دائر کر نیکی کوشش کرتے ہیں اون کو مار پیٹ کر کے الزام کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں - ۱۰ - جولائی کو افضل بی کے ساتھ ریپ ( Rape ) کرنے کی کوشش کی گئی تھی اسکے باوجود ۱۶ - جولائی کو ان کو مار پیٹ کر کے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ اپنی درخواست واپس لے لیں - اور انکو یہ دھمکی دی گئی کہ اگر درخواست

واپس نہ لینگے تم و ہر مقدمات چلائے جائیں گے - وغیرہ وغیرہ - ینکنا اور بھدیرا جو مقامی ٹینٹس ہیں انکے ساتھ ۱۷ - ۱۸ لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور ان پر جھوٹے مقدمات دائر کئے جاتے ہیں کہ زمیندار کی گڑھی پر انہوں نے حملہ کیا ہے لیکن وہ سراسر جھوٹ ہے - ان واقعات کو جب کبھی اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے تو ڈپٹی ہوم منسٹر صاحب واقعات کو صحیح نہیں مانتے ہیں - آنریبل ہوم منسٹر شری دگمبر راؤ بندو فرماتے تھے کہ کسی واقعہ کا اظہار کرنے سے پہلے آپ خود وہاں جائیے - تحقیقات کیجئے اور اون واقعات سے خود مطمئن ہونے کے بعد اس کے متعلق رپریزنٹیشن کیجئے تو میں اون کی تحقیقات کرونگا اور جب میری تحقیقات میں کسی کی نا جائز حرکت ثابت ہو جائے تو میں ضرور اس کے خلاف اقدام کرونگا - اون کے اس کہنے کی بناء پر ہمارے لیڈر شری وی - ڈی - دیشپانڈے نے بھی ہم کو ہدایت کی کہ ذاتی طور پر انکوائری ( Enquiry ) کرنے کے بعد جب واقعات صحیح ثابت ہوں تو رپورٹ کیجایا کرے - چنانچہ میں اس واقعات سے متعلق تحقیقات کے لئے خود شری وی - ڈی - دیشپانڈے کو بھی لے گیا ہوں - ۱۶ - اگست کو شری وی - ڈی - دیشپانڈے کے آنے کی اطلاع پا کر سب انسپکٹر نے وہاں کے لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی - انکو دھمکیاں دی گئیں کہ ان کے خلاف بیان دیا گیا تو اچھا نہیں ہوگا - وہاں ہم نے گھر گھر پھر کر حالات معلوم کئے - زخمی لوگوں کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا - وہاں سے آکر ہم لوگوں نے رپورٹ پیش کی لیکن جب ہم کو جواب دیا جاتا ہے تو وہی میں دیا جاتا ہے - ہم جب کوئی سوال پیش کرتے ہیں اوس کے جواب میں مقامی عہدہ داروں کی پشت پناہی کیجاتی ہے - میں یقین دلاتا ہوں کہ وہاں کے حالات کو دریافت کرنے کے لئے خود منسٹر صاحب ہمارے ساتھ چلیں تو وہ ہمارے بیان کی تصدیق کرسکیں گے - میں اون واقعات کو ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں - ان لوگوں کو اس طرح مارا پیٹا گیا ہے کہ حیوانوں کو بھی کوئی اس طرح مارنا پیٹنا پسند نہ کریگا - ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے مجبوراً رعایا اراضیات سے بیدخل ہو رہے ہیں - جب ایسے واقعات ہم اسمبلی میں سوال کے طور پر پوچھتے ہیں تو وہاں کے مقامی افسروں کی رپورٹ کی بناء پر کہا جاتا ہے کہ ہمارا رپریزنٹیشن غلط ہے - اس سلسلہ میں آنریبل چیف منسٹر صاحب کو متوجہ کیا جائے تو وہ کلکٹر کو لکھتے ہیں کہ کلکٹر خود فوراً اس مقام پر پہنچ کر تحقیقات کریں اور یہ انتظام کریں کہ ٹینٹس بیدخل نہ ہونے پائیں لیکن کلکٹر وہاں نہیں جاتے ہیں - مجھے حیرت ہے کہ کلکٹر چیف منسٹر کے آرڈر نہیں سنتے ہیں - سپرنٹنڈنٹ کو لکھا جاتا ہے تو وہ آخر وقت میں آتے ہیں - مادھوراؤ سب انسپکٹر کے کئے ہوئے مظالم کے متعلق اسمبلی میں سوالات کئے گئے تو جواب دیا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے - رپریزنٹیشن جھوٹ ہے - میں آنریبل منسٹر کو دعوت دوں گا کہ وہ میرے ساتھ چلیں اور رعایا کے سامنے تحقیقات کر کے اون کے سامنے کہہ دیں کہ یہ رپریزنٹیشن جھوٹ ہے - اگر رپریزنٹیشن جھوٹا ثابت ہو جائے تو میں اوس کے لئے تیار ہوں کہ ہم پر اس پاداش میں مقدمہ چلایا جائے - آنریبل ہوم منسٹر ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم خود مقام واقعہ پر جائیں اور تحقیقات کر کے مطمئن ہونے کے بعد انکے سامنے ایسے واقعات پیش کریں جو حقیقت پر مبنی ہیں - جب ہم ایسا کرتے ہیں

تو اوس پر کوئی توجہ نہیں کیجاتی اور کہا جاتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ آخر اسمبلی کے ارکان کی باتوں کا بھی کوئی وزن ہے یا نہیں۔ جب ہم عہدہ داروں سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ پیدخل کریں۔ حتیٰ کہ وہ نام بھی بتاتے ہیں کہ شری وینکٹ رنگ ریڈی صاحب نے حکم دیا ہے۔ چیف منسٹر صاحب کا آرڈر بھی کیوں نہ ہو ہمیں رنگ ریڈی صاحب کا آرڈر ہے ہم اسکی تعمیل کریں گے۔ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی۔ ان کا یہ کہنا ہے۔

منسٹر ڈپٹی اسپیکر :— مختصر طور پر بیان کیجئے۔

شری سری ہری (کنوٹ) :— کیا ان واقعات کو ثابت کیا جاسکتا ہے ؟

شری کے۔ ایل۔ نرسمہا راؤ :— ہاں میں ثابت کرنے کے لئے تیار ہوں۔ میں نے خود کہا ہے کہ اگر نہ ثابت کر سکوں تو میرے خلاف مقدمہ چلایا جائے۔ پھر حال حکومت کے اس قسم کے جو جوابات ہوتے ہیں انکے خلاف میں پروٹسٹ (Protest) کرتا ہوں اور حکومت سے میری یہ استدعا ہے کہ وہ اس قسم کے واقعات کی مناسب تحقیقات کرائے اور لوگوں کو ناجائز طور پر جو ستایا جا رہا ہے اوس کے انسداد کی جانب متوجہ ہو۔ اتنا کہتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔

ڈپٹی ڈی ایچ ایم منیسٹر (شری. شری نیواس راء وہ خلیکار):— سہی کر سر، اس شارڈ نوڈیس مں جو سوال کیا گیا ہے اور اس کے بارے مں جو بھس کی گئی ہے اس کے مٹالیک مں یہ بتانا چاہتا ہں کی جو کھ کھا گیا وہ اس تری کے سے کھا گیا ہے کی مھج اےک جلم ہوتا ہے اور ٹننٹس کو ناچایج تاور پر بے دھل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پولیس والے جلم کر رہے ہں اور منیسٹرس ان کو ڈیفنڈ کر رہے ہں اور ہالانک اسے بلی کے بھت سے ان رے بل مے برس وہاں گئے اور انھوں نے تھکی کا ت کی اس کے با د بھی اس رپورٹ مں بروسا نہی کیا جاتا، اس تری کے سے بھس کی گئی ہے۔ پرسوں اسے بلی مں جو سوال آیا تو اس وک ت بھی اسی ت رھ ہے کھا گیا تھا۔ کھ اس کے کی ہم کو بھی ایلجام اےک دوسرے پر آید کرے، مسلا کیا ہے اس کو سمجھنے کی جھرت ہے۔ مسلا یہ بیان کیا جاتا ہے کی وہاں پر کئی جمی نا ت پر کھ ٹننٹس ہں اور ان کو وہاں کے جمی نا دار پولیس اور مال کے اوہ دے داروں کی ام دا د سے جب دے سٹی بے دھل کر رہے ہں اور ٹننٹس پر مچالیم ڈایے جا رہے ہں۔ پولیس کے ہد ت ک جمی نا ت کے بارے مں جو سوال آتے ہں تو مں یہ بتانا چاہتا ہں کی ٹننٹی کے بارے مں ان کو اھ کام دیے گئے ہں کی انھوں نے کھ یا ٹننٹی کے کھ گے آتے ہں تو وہ کھ اس کے کی کو بھی اےک دام کرے یام دا خ ل ت کرے اوہ۔ داران مال سے سا ف تاور پر پھ لے کی اس جمی نا کا کون پروٹکٹڈ ٹننٹ ہے اور کون واک بھی کا بھی ہے اور بتاور کھ دے کو بھی اےک دام اپنی ترف سے ن کرے۔ اس واکے کے بارے مں اوہ۔ دے داران پولیس نے کیا رے یا اے ختیار کیا اس کو بل تانا چاہتا ہں۔ وہاں کی کھ جمی نا ت کے بارے مں شیکا ی ت کی گئی کی یہ جمی نا دار ہم کو بے دھل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بارے مں د ریا ف ت کھ ہئی۔ اس کے با د وہاں کے تھ سلی نے ان کے ٹننٹ ہونے کے بارے مں انکار کیا اور جاحیر کیا کی ان کے مالک کو بھی جلا رے ڈی ہں۔ اس کے بارے مں جب پولیس مں پھ ل

मर्तबा दरखास्त पेश हुआ उसमें ज्यादा तर शिकायत मुन्तजिम माधवराव के बारे में की गयी है लेकिन वह जिस तसवीर में बहुत आखरी स्टेज में आता है। पहले जिस मुकदमे की तफतीश वहां के सर्कल इन्स्पेक्टर और अ. अ. पी. कर रहे थे। पहली मर्तबा जब दरखास्त पेश हुआ तो सर्कल इन्स्पेक्टर ने तहसीलदार से दरयाफ्त कि उस जमीन का प्रोटेक्टेड टेनन्ट कौन है। और जिसके नाम टेनन्सी सर्टिफिकेट अजरा किये गये हैं। उन्होंने जबाब दिया कि जिसके बारे में टेनन्सी सर्टिफिकेटस किसी के नाम पर अजरा नहीं किय गये हैं और जिसके मालिक जन्ना रेड्डी हैं। सर्कल इन्स्पेक्टर ने फिर पूछा कि गो के टेनन्सी सर्टिफिकेटस किसी को नहीं दिये गये रेकार्ड के लिहाज से हक्के काबजीन कौन है जिसकी सराहत की जाय ताकि हमको काबीज के हुक्म की हिफाजत करने में मदद मिल सके। जिसके बाद जबाब दिया गया और १० जुलाजी १९५४ को कलेक्टर ने मौकेपर तफतीश करते हैं। उन्होंने लिखा है कि—

....“I am therefore to conclude that this is a case of ‘illegal obstruction’ under the repealed Section 74 of the Land Revenue Act for which there is no relief from the Revenue Courts. As the petitioners could not fulfil the conditions of Section 5 of the Tenancy Act, their possession on the said land is deemed illegal and amounts to trespass. Hence they are hereby ordered to be evicted therefrom under Section 98 read with Section 32(4) of the Tenancy Act, 1950.”

यह हुक्म १० जुलाजी १९५४ को होता है। कलेक्टर ने यह भी उनसे कहा कि वे ट्रेसपासर्स हैं। यह हुक्म सही है या गलत है जिसके बारे में मैं यहां बहस करनेवाला नहीं हूं और जिस डिपार्टमेंट को तरफ से मैं जबाब दे रहा हूं उस डिपार्टमेंट को यह देखने का हक नहीं है कि दरअसल उस जमीन पर कोजी जायज तौर पर काबीज है या नहीं। मतलब यह है कि जिस तरह के हुक्म पुलिस डिपार्टमेंट के ओहदेदारों को दिये गये हैं। कलेक्टर ने हुक्म देने के बाद भी जो लोग टेनन्टस समझते थे उनको मायूसी हुई और उसके बाद १५ जुलाजी को ‘सो काल्ड टेनन्ट्स’ ने दूसरे तरीके अस्तियार करने शुरू किये। जन्ना रेड्डी के मकान में दाखिल हो कर कुछ मदाखलत वगैरा के वाकयात किये जाते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वाक्या गलत है। लेकिन जिसके बारे में सर्कल इन्स्पेक्टर ने तफतीश की है और वहां पर अ. अ. पी. मौजूद थे। जो माल मसरूख था वह उनसे बरामद किया गया और उसके बाद अदालत से मुहल्लत ली गयी। अक दफा सात दिन की मुहल्लत ली और फिर उनको अदालत में पेश किया गया। जो अलजामात लगाये गये कि उनको पुलिस के हिरासत में मारा गया, पीटा गया और जुल्म हुआ उसके बारे में दरयाफ्त की गयी तो पता चला कि उनके बयानात अदालत में कलमबंद किये गये हैं। अदालत ने पुलिस ने उनके साथ कोजी नारवां सुलूख किया है या नहीं इसके बारे में सवाल किया लेकिन उनकी तरफ से कोजी शिकायत नहीं की गयी। और न कोजी जल्म के बारे में नोट कराजी। उन्होंने जिसके बारे में कोजी बयान नहीं किया। जिसके बाद भी अगर यहां पर शिकायत की जाय तो वह कहां तक सही हो सकती है जिस पर ऑनरेबल मॅम्बर्स को गौर करना चाहिये। मैंने अपने जवाब में कोजी मॅम्बर झूठ कह रहे हैं ऐसा लज्ज अिस्तेमाल नहीं किया था। मुझे मालूम है कि ऑनरेबल मॅम्बर्स वहां गये हैं। थोड़ी देर ठहरे होंगे लेकिन सितही नजर से वाक्य को देखा होगा।

लेकिन जिस तरीके से वाक्यों की दरयाफ्त करना चाहिये उस तरीके से अन्होंने नहीं की होगी जिसलिये सही वाक्या उनके अिल्म में न आया हो। यह हो सकता है। मैंने रिपोर्ट को पूरी तरह पढा और बाद में ही जवाब देने के लिये खडा हुआ। मैं इसका आदी नहीं हूँ कि ओहदेदारों के नाजायज करतूतों को पीठपर डालकर फिहं। मैंने जवाब दिया है कि जब कभी कोअी गलती महसूस करता हूँ या कहां तक मेरे कान्वान्स का तालुक है—मुमकिन है कभी मैं भी गलती करता हूँ—लेकिन आम तौर पर यह कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे गलत रिपोर्ट मालूम हुअी तो उस पर कडे रिमाक्स कर के वापिस करता हूँ और अेक के बाद दूसरे से और दूसरे के बाद तीसरे से दरयाफ्त करता हूँ ताकि मुझे अितमीनान हो। इस रिपोर्ट को मैंने पढा तो मेरे कान्वान्स की हद तक मुझे इसमें अैसी कोअी चीज नहीं मालूम हुअी जो कोअी बनाअी हुअी चीज हो। जिसलिये जहां तक मेमोरेंडम का तालुक है दो चीजों की शिकायत की गअी है। अेक यह कि झूठ मुकद्मात बनाये गये और पुलिस ने हिरासत में मारा पीटा। इसके बारे में मैं कह चुका हूँ। दूसरी चीज यह कही गअी है कि अेक औरत पर हमला कर के उसकी बेअिज्जती करने की कोशिश की गअी। इसके बारे में मेरे पास जो रिपोर्ट है उसकी बिना पर मैं अितना ही कह सकता कि इसमें से अितना ही वाक्या सही है कि वह औरत कहीं चप्पे पर कपडे धोने या और किसी काम के लिये गअी थी, वहां चंद लोग जमा हुअे और उसके बारे में वहां पर नाशायस्ता अल्फाज अिस्तेमाल किये गये। इस हद तक वाक्या हुआ है। लेकिन इसके आगे का वाक्या कि उसपर रेप करने की कोशिश की गअी, जो रिपोर्ट मेरे सामने है उसके लिहाज से अैसा वाक्या नहीं हुआ है। आगे चल कर रिपोर्ट में अन्होंने बयान किया है कि परसनल अेक्वायरी मैंने की है और इसमें मुझे अिसी हद तक सही वाक्या मालूम हुआ। इसके बाद का स्टेज गलत मालूम होता है।

شری کے - وینکٹ رام راؤ (چناکنڈور) :— ہم کو سپلیمنٹری (Supplementary) سوالات کا موقع کب دیا جائیگا ؟

مسٹر ڈپٹی اسپیکر :— خود جوابات تفصیل سے کہے جارہے ہیں تو سپلیمنٹری سوالات کی کیا ضرورت ہے ؟

شری کے - وینکٹ رام راؤ :— یہ بتلایا جائے کہ کیا کلکٹر کے فیصلہ کی تعمیل ہو رہی ہے ؟

श्री. श्रीनिवासराय अेखेलीकर :—कलेक्टर के हुक्म की तामिली हुअी जिसलिये झगडा शुरू हुआ। कलेक्टर की तामिली में जब लोग वहां काश्त के लिये गये और कब्जा पाये उस वक्त झगडा शुरू हुआ। जो टेनन्ट्स समझते थे उनका कब्जा न होने देने के लिये कोशिश की गअी। और कलेक्टर के हुक्म पर नाजायज जुर्म करने की किसी को अिजाजत नहीं दी गअी या उनको रोका गया। पुलिस को वहां यह भी अित्तिला मिली थी कि वे लोग पांच छः सौ लोगों को लेकर जमीन पर कब्जा लेने के लिये आनेवाले हैं। जिसलिये पुलिस फोर्स लेकर सर्कल अिन्स्पेक्टर्स और सबअिन्स-पेक्टर वहां पहुंचे। मौके पर जाकर अन्होंने दरयाफ्त की तो मालूम हुआ कि वहां पर नहीं लेकिन दूसरे अेक गांव में लोग जमा हो रहे थे। और जो लोग जमा हुअे थे उनके खिलाफ १०७ की कार्रबाअी की गअी।

जिसके बाद कब्ज के बारे में कुछ कहा गया है। वह मेरे मुतालिक सवाल नहीं है। लेकिन

ایس رپورٹ سے جیتنا مسو پتا چلتا ہے اوس پر سے میں کہنا چاہتا ہوں ۔

مسٹر ڈپٹی اسپیکر:— رول ( Rule ) ایسا ہے کہ جواب مختصر ہونا چاہئے ۔

شری اے۔ گرواریڈی ( سدی بیٹھ ) :— مسٹر اسپیکر سر ۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے میں اس رپورٹ سے جاہر ہوتا ہوں ۔

مسٹر اسپیکر سر :— مسٹر اسپیکر سر ۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے میں اس رپورٹ سے جاہر ہوتا ہوں ۔

شری اے۔ گرواریڈی ( سدی بیٹھ ) :— مسٹر اسپیکر سر ۔ چونکہ وقت ہو رہا ہے اس لیے میں اس رپورٹ سے جاہر ہوتا ہوں ۔

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟

شری اے۔ گرواریڈی :— اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہانی پترک میں انکے نام ہیں تو آپ کیا کریں گے ؟



श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—यह वाक्या गलत है। सुपरिटेण्डेंट ने गलत रिपोर्ट की है ऐसा मालूम हुआ तो उसके खिलाफ बराबर अॅक्शन लूंगा।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मैंने अपनी दरखास्त में लिखा था कि सितारामपूर के छः आदमियों को गिरफ्तार कर के आलेंद्रू स्टेशन पर जब ले जाया गया तो माधवराव और लक्ष्मी रेड्डी ने उनको मारपीट की। क्या इसके बारे में आपने तहकीकात की और आपके पास क्या रिपोर्ट आती है २६ अगस्त १९५४ को मैंने यह रिपोर्ट वहां से आने के बाद आपके पास दी थी।

श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—मैंने कहा कि माधवराव ने इस वाक्य की तफ्तीश नहीं की बल्कि सर्कल इन्स्पेक्टर ने की है। माधवराव बहुत आखिरी स्टेज में आये हैं। जिस वाक्य का जिक्र किया गया है उसमें माधवराव का सवाल नहीं है। जिसलिये मारपीट का वाक्या गलत है ऐसा कहा गया है।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—सर्कल इन्स्पेक्टर के साथ मैं खुद वहां गया था और सब-इन्स्पेक्टर भी वहां था। उनको जिस आदमी को मारा गया था उसकी जखम दिखायी गयी तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में मैं तहकीकात करूंगा। क्या उन्होंने इसके बारे में आपको अितिला दी है ?

श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—आप कहते हैं कि जखम थे। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर अदालत के सामने उन लोगों ने शिकायत क्यों नहीं की जब कि उनको मौका दिया गया था।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—कोयी वकील वहां नहीं था, उनको डर था कि अदालत से निकलने के बाद फिर से उनको मारपीट होगी जिसलिये उन्होंने कोयी बयान नहीं दिया, क्या ऐसा नहीं हो सकता ?

श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—इस वाक्य के पसमंजर को देखा जाय तो मालूम हो सकता है। अम. अल. अंज. और अम. पीज. इसके बारे में कह रहे हैं। वे हर जगह कह सकते हैं कि पुलिस ने जुल्म किया —————

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :— हम लोग वाक्या होने के बाद वहां गये थे।

श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—वह तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब अम. अल. अंज. और अम. पीज. इसके बारे में कह रहे हैं, पुलिस के बारे में हर जगह वह कह सकते हैं यहां तक कि यहां आकर भी कहा जा रहा है तो वहां पर अदालत में कहना जरूरी क्यों नहीं समझा गया ?

شری کے - ایل - نرسما راؤ :- وکیل کو پیش کیا گیا تھا لیکن منصف نے وکالت پیش کرنے سے منع کر دیا - ملزم وہیں رہتے ہیں انکی دستخط وکالت نامہ پر لینے سے انکار کیا جاتا ہے - وکیل کو بحث کرنے کا موقع نہیں دیتے ہیں -

श्री. श्रीनिवासराय अखेलीकर :—मैंने वकील के नाते पच्चीस साल प्रैक्टिस की है। मैं नहीं समझता कि अदालत में आने से किसी वकील को रोका जा सकता है। मैं इसको सही नहीं समझता।

شری کے - ایل - نرسما راؤ :- وہ قنولات بھی میرے پاس ہیں میں پیش کرونگا -

श्री. श्रीनिवासराव अखेलीकर:—अदालत किसी को वकील होने से रोकती है या वकालत नामा लेने से रोक सकती है ऐसा जिस जमाने में हो सकता है जिस बात को मैं सही नहीं समझ सकता।

شری عبدالرحمن:— کیا یہ صحیح نہیں کہ .....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر:— جو ممبر پہلے سے سوال کرنے کے لئے انٹیمیشن (Intimation) دیتے ہیں وہی سوال کر سکتے ہیں۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—अगर मैं आपको यह साबित कर दूँ कि वहाँ के जिन लोगों ने मुझे टेलीग्राम किया था कि ऐसा जुल्म यहाँ हो रहा है आप फौरन आइये तो आपको भी पीटा गया है मैं वह टेलीग्राम आपको बता सकता हूँ और आप और हम दोनों वहाँ जाने के बाद यह अगर साबित हो जाय तो क्या आप रिपोर्ट को झूठ नहीं मानेंगे।

श्री. श्रीनिवासराव अखेलीकर:—मैं टेलीग्राम आने से किसी चीज को सही नहीं समझ सकता वाक्या होने की सूरत में ही सही समझ सकता हूँ। क्योंकि लोग आपको भी गलत बावर करने की कोशिश कर सकते हैं। वाक्य की दर्यापत करने के बाद अगर सही पाया गया तो सही समझ सकता हूँ।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—चूँकि लोगों ने टेलीग्राम भेजा था कि आपको मारापीटा गया है, जखमों आपको आजी थीं। तब मैं खुद वहाँ गया और सर्कल इन्स्पेक्टर को भी दिखाया तो क्या आप इसको सही नहीं समझ सकते।

श्री. श्रीनिवासराव अखेलीकर:—मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनको मारापीटा गया और जखम हुआँ क्या वे दवाखानों में रूजू हुआँ थे।

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—खुशकिस्मती से उन्हें अतना नहीं मारा गया था जिससे वे हास्पिटल में रूजू हो जायें। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मारा ही नहीं गया था।

श्री. श्रीनिवासराव अखेलीकर:—अदालत में बयान नहीं किया जाता, अस्पताल में रूजू नहीं होते और जब तक यह साबित नहीं होता तो कैसे सही समझा जाता? न अदालत में बयान किया जाता है, न दवाखाने में रूजू होते हैं और कहते हैं कि मारा गया पीटा गया, जखम हुआँ, टेनन्सी सर्टीफिकेट्स नहीं हैं और मालगुजारी की अदायी की रसायद भी नहीं, लेकिन फिर भी आप कहें कि कब्जा हमारा है तो उसको कैसे माना जा सकता है।

*The House then adjourned till Nine of the Clock on Saturday, the 19th September, 1954.*